● वर्ष-3

● अंक-112

रायपुर, मंगलवार 19 दिसंबर 2023

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› पेड़-पौधे भी देते है सीख ...

जमने लगी ओस की बूंद

गिर रहा मौसम का पारा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। ठंड बढ़ जाने से जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। ठंड का प्रकोप इतना है कि लोगों को घर से निकलने के लिए सोचना पड़ जाता है। पुरे क्षेत्र में घने कोहरे के साथ ओस की बूंदे भी जमने लगीहैं। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के कारण पुरे प्रदेश में ठंड का प्रभाव अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि के बारशि तो नहीं होगी लेकिन प्रदेश भर में बदली छाए रहने के कारण ठंड से राहत मिल सकती है। वैसे आज प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में ठिठुरन वाली ठंड और ज्यादा पड़ने वाली है , यह 21 दिसम्बर तक बने रहने का अनुमान लगाया है। फ़िलहाल अभी मौसम में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री के आसपास गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे में अंबिकापुर जिले में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो राज्य का सबसे कम तापमान वाला जिला रहा। राजधानी रायपुर समेत मध्य कक्षेत्रों में भी रात में एक से डेढ़ डिग्री तक तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। शहर के बाहरी इलाकों के साथ-साथ भीतरी इलाकों में ठंड का असर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में रायपुर का रात का तापमान 13.6 और माना का 12.6 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया, दिन में भी तापमान सामान्य से एक डिग्री कम होने के कारण अब लोग गर्म कपड़े पहन कर ही घरों से बहार निकल रहे है।

प्रदेश के जिलों का तापमान

छत्तीसगढ़ में बीते रविवार को दर्ज किए गए तापमान की बात करें तों। राजधानी रायपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 27 से सब लोग 6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री दर्ज किया गया था इसके साथ ही रायपुर के ग्रामीण इलाका माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.02 डिग्री दर्ज किया गया था। शहर और माना एयरपोर्ट पर तापमान में लगभग 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही बिलासपुर का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री रहा है।? पेंड्रा रोड कार्यक्रम तापमान 23.8 डिग्री न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री, अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री, इसके साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाके का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री तक दर्ज किया गया है। इसके साथ ही राजधानी से नजदीक जिले दुर्ग का अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री दर्ज किया गया है।

संसद के 73 सदस्य निलंबित

अब तक करीब 100 विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन सोमवार (18 दिसंबर) को लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के कुल 78 सांसदों को निलंबित किया गया. ये सभी सांसद 13 दिसंबर को हुए संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे. दोपहर में लोकसभा में विपक्ष के कुल 33 सांसद बचे सत्र के लिए निलंबित किए गए. अब शाम को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के 45 सांसदों को निलंबित कर दिया.

इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसद निलंबित किए गए थे. राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को सस्पेंड किया गया था. शीतकालीन सत्र से अब तक कुल मिलाकर 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है. लोकसभा में अब तक कुल 46 सांसद सस्पेंड हुए हैं. राज्यसभा में भी कुल 46 सांसद सस्पेंड हुए हैं.

संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया. इनमें नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9, डीएमके के 9 और 4 अन्य दलों के सांसद शामिल हैं. सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गई.

लोकसभा में सस्पेंड हुए 33 सांसदों के नाम- लोकसभा के 33 सांसदों में कांग्रेस के 7 सदस्य- अधीर रंजन चौधरी, एंटो एंटोनी, के मुरलीधरन, के सुरेश, अमर सिंह, राजा मोहन उन्नीथन और गौरव गोगोई को शेष सत्र के लिए निलंबित किया गया है. टीएमसी के निलंबित सदस्यों में कल्याण बनर्जी, अपरुपा पोद्दार, प्रसून्न बनर्जी, सौगत राय, शताब्दी राय, असित कुमार मंडल, प्रतिमा मंडल, काकोली घोष दस्तीदार और सुनील कुमार मंडल शामिल हैं. डीएमके के 9 सदस्यों को निलंबित किया गया है. इनमें टी आर बालू, ए. राजा, दयानिधि मारन, जी सेल्वम, सीएन अन्नादुरई, डॉ टी सुमति, के वीरासामी, एस एस पल्नी मणिक्कम और रामलिंगम शामिल हैं. आईयूएमएलके ई टी मोहम्मद बशीर और के नवासिकानी को निलंबित किया है - आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन, छुष्ठ के कौशलेन्द्र कुमार और वीसीके तिरुवक्कससर भी निलंबित सदस्यों में शामिल हैं.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी के प्रस्ताव पर सदन ने कांगेस के तीन अन्य सांसदों के. जयकुमार, विजय वसंत और अब्दुल खालिक को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक के लिए निलंबित किया.

14 दिसंबर को ये सांसद हुए थे निलंबित- लोकसभा से कांग्रेस के 9, सीपीआई (एम) के 2, डीएमके और सीपीआई के एक-एक नेता को सस्पेंड किया गया था. कांग्रेस सांसद टी एन प्रतापन, हिबी ईडन, जोथिमानी, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस , मनिकम टैगोर, एमडी जावेद, वीके श्रीकंदन और बेनी बेहनन सस्पेंड किए गए हैं.

निलंबित विपक्षी सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन

कांग्रेस के जयराम रमेश, के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कुल 34 विपक्षी सांसद; टीएमसी के सुखेंदु शेखर रे और शांतनु सेन; राजद के मनोज कुमार झा को आज शेष सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा से निलंबित कई विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। शीतकालीन सत्र के शेष समय के लिए राज्यसभा से कई विपक्षी सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि 34 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। 11 सांसदों का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। आज कुल 45 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। वे नहीं चाहते थे कि सदन सुचारू रूप से चले, ये उनकी पूर्व नियोजित रणनीति थी। राज्यसभा से निलंबित किए जाने पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि मैं भी उनमें शुमार हूं।

कांग्रेस के क्राउड फंडिंग कैंपेन में आई दिक्कत

लिंक पर क्लिक करते ही खुल रहा भाजपा का डोनेशन पेज

नई दिल्ली। कांग्रेस का डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग कैंपेन सोमवार (18 दिसंबर) को लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के अंदर टेक्निकल खामियों से कुछ देर के लिए रुक गया. ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहल की घोषणा करने से पहले डोमेन नाम को रजिस्टर्ड नहीं कराया था, जिसके चलते ये दिक्कत आई. हैरानी वाली बात ये थी कि कांग्रेस के डोनेशन पेज डोनेट फॉर देश डॉट ओआरजी पर क्लिक करने से विजिटर्स बीजेपी के डोनेशन पेज पर पहुंच जाते थे. इसके अलावा, डोनेट फॉर देश कैंपेन के नाम से एक रिलेटेड डोमेन न्यूज वेबसाइट OpIndia की ओर से एक्वॉयर्ड किया गया है. हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि टेक्निकल ग्लिच (तकनीकी खामियों) को दूर कर लिया गया है. कांग्रेस नेता और पार्टी की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा है. सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर लिखा, सबसे पुरानी पार्टी के डोनेशन कैंपेन शुरू करने के बाद से बीजेपी घबराहट की स्थिति में है. सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर हिंदी में लिखा, निरंकुश सत्ता, सारी संस्थाएं, सारे संसाधन और अधिकतम पैसा होने के बावजूद बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है जब कांग्रेस ने डोनेशन कैंप शुरू किया, तो न सिर्फ बीजेपी के लोग घबरा गए, बल्कि उनके सिस्टम ने फर्जी डोमेन बनाना और विजिटर्स को भ्रमित करना भी शुरू कर दिया. वैसे, हमें कॉपी करने के लिए धन्यवाद. आपका डर देखकर अच्छा लगा. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को पार्टी के क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत की. खरगे ने इस दौरान 1 लाख, 38 हजार रुपये डोनेट भी किए. खरगे ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, एक महीने की तनख्वाह चली गई. खरगे ने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता से दान लिया था. डोनेशन कैंपे को लेकर कांग्रेस ने कहा, इस कैंपेन का मकसद समान संसाधन वितरण और अवसरों से समृद्ध भारत बनाने के लिए पार्टी को सशक्त बनाना है. वेबसाइट पर पेमेंट लिंक डोनर्स को कांग्रेस पार्टी के 138 साल पूरे होने के अवसर पर 138 या 1380 या 13,800 का योगदान करने के लिए प्रेरित करता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कांग्रेस ने लिखा- एक कैंपेन से परे, यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत करने, असमानताओं को पाटने और समृद्ध लोगों का पक्ष लेने वाली सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़े होने की प्रतिबद्धता है.

प्रमुख समाचार

महाराष्ट्र विधान परिषद- दाऊद के 'रिश्तेदार' से संबंध के लेकर भाजपा-विपक्ष आमने-सामने

मुंबई। महाराष्ट्र विधान परिषद में सोमवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सदस्य एकनाथ खडसे के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक मंत्री ने 2017-18 में भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक परिवार के विवाह समारोह में हिस्सा लिया था। फडणवीस ने आधारहीन आरोप लगाने के लिए खडसे से विधान परिषद में माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह आरोप लगाए गए क्योंकि उद्धव ठाकरे सदन में मौजूद थे। राकांपा के शरद पवार गुट के खडसे ने सदन में कैबिनेट मंत्री की एक शादी समारोह में शामिल होने की कथित तस्वीरें दिखाईं और आरोप लगाया कि यह परिवार 1993 के मुंबई सिलसिलेवार धमाके के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। विधान परिषद की सभापति नीलम गोरे ने निर्देश दिया कि मंत्री का नाम कार्यवाही से हटा दिया जाए। उन्होंने विपक्ष की चर्चा की मांग भी खारिज कर दी।

शराब घोटाला मामला: ईडी ने केजरीवाल को भेजा दूसरा समन, 21 को पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है. जानकारी के अनुसार ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है. इससे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया था. लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को गैरकानूनी बताकर नोटिस वापिस लेने की मांग की थी. ईडी के नए नोटिस पर आप सांसद संदीप पाठक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये केस पूरी तरह से फर्जी केस है. इस केस में कुछ भी नहीं है. पीएम मोदी जी से कोई भी सवाल करता है, पीएम उसे गिरफ्तार करवाते हैं. पीएम अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं और सबसे ज्यादा डरते हैं. उनके सामने कोई सरेंडर करता है तो पीएम उसे क्लीन चिट दे देते हैं. अरविंद केजरीवाल जी विपश्यना में जाने वाले हैं और वकील नोटिस स्टडी रहे हैं. आगे देखते हैं कैसे होगा.

मैंने 17 साल अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री यादव के नेतृत्व में मुझसे भी बेहतर काम हो: चौहान

भोपाल। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ. सत्र के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की. उन्होंने सभी नए विधायकों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि मेरा पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा. खबरें हैं कि मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं. प्रेस कान्फ्रेंस में शिवराज ने कहा, विधानसभा में एक तरफ पुराने और अनुभवी साथी भी विधायक चुनकर आए हैं तो वहीं नई पीढ़ी का भी पर्याप्त समावेश है. उन्होंने कहा, एक और आनंद का विषय है. इस बार पीढ़ी परिवर्तन भी हुआ है. मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं तो नेता प्रतिपक्ष भी उमंग सिंगार हैं. पीढ़ी परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो दोनों पक्षों में देखने को मिल रही है. हमें इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए. शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा.

संसद की सुरक्षा में चूक मामले में जनहित याचिका, पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में जांच की मांग

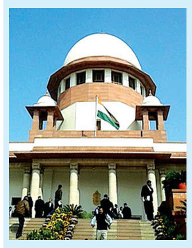

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा में हुई चूक की शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश की अगुआई में अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया गया है। तीन दिसंबर को सागर शर्मा और मनोरंजन डी नाम के दो व्यक्ति शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक दीर्घा से लोकसभा के कक्ष में कूद गए थे, उस दौरान उन्होंने कनस्तरों से पीला धुआं छोड़ा था और नारेबाजी की थी। लगभग उसी समय दो अन्य लोगों अमोल शिंदे और नीलम देवी ने संसद भवन परिसर के बाहर तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए कनस्तरों से रंगीन धुआं छोड़ा था। पांचवें आरोपी ललित झा ने कथित तौर पर परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए। यह जनहित याचिका वकील याचिकाकर्ता अबू सोहेल ने अधिवक्ता श्रुति बिष्ट के माध्यम से दायर की।

कोरोना की वापसी, केंद्र ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी

केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के काराकुलम में हल्के लक्षणों वाली 79 वर्षीय महिला से लिए गए नमूने में नए कोरोनोवायरस वेरिएंट जेएन.1 का पहला मामला सामने आने के बाद केंद्र ने राज्यों को एक सलाह जारी की। इससे पहले, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के एक यात्री में सिंगापुर में एनजे 1 सब-वेरिएंट का पता चला है। सलाह में कहा गया है कि आगामी त्योहारी सीज़न को ध्यान में रखते हुए, श्वसन स्वच्छता के पालन द्वारा बीमारी के संचरण के जोखिम को कम करने के लिए अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। सलाह में राज्यों को नियमित आधार पर सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में जिलेवार इन्फ्लूएंज जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मामलों की निगरानी और रिपोर्ट करने और एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच में विवरण अपडेट करने का निर्देश दिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि राज्यों को सभी जिलों में पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

भाजपा ने चौंकाया तो महाराष्ट्र में भी था!

अमिताभ श्रीवास्तव

तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौंकाने वाली परिपाटी को अंजाम दिया। हालांकि तीन राज्यों में बहुमत की सरकार का गठन होने जा रहा था, फिर भी किसी एक नाम को लेकर कयास लगाना गलत साबित हुआ और नया नाम ही सामने आया। यदि अतीत में देखा जाए तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम भी अचानक ही सामने आया था और वह भी दूसरे दल तथा कम विधायकों के नेता होने के बावजूद उसे अधिक महत्व दिया गया। संभव है कि हर घोषणा के पीछे कोई राजनीति अवश्य रही है, लेकिन जनआकांक्षाएं व्यक्ति से अधिक काम को महत्व देती हैं।

भाजपा के विधानसभा चुनाव इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो कभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने में निवर्तमान मुख्यमंत्री की पराजय हो जाती है। उन्हें एक और अवसर नहीं दिया जाता है। कभी उत्तरांचल में मुख्यमंत्री के चुनाव हारने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर उपचुनाव से दोबारा निर्वाचित किया जाता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक ही व्यक्ति को बार-बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाता है, तो गुजरात में कई मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहता है। स्पष्ट है कि भाजपा अपनी जरूरत के अनुसार अलग-अलग चेहरों पर दांव लगाती है। साथ ही उनसे परिणाम भी लेती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और उत्तराखंड इस बात के उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में पिछले साल शिवसेना के टूटे हुए गुट पर भाजपा ने अपना पासा फेंका और सरकार बनाई। यहां तक कि अपनी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को उपमुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया। अवश्य ही इसके पीछे पार्टी की अपनी रणनीति और सरकार चलाने का तरीका कहा जा सकता है। मगर जनसरोकार के आगे यह अखबारों की चंद सुर्खियों से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके आगे अपेक्षाओं का लंबा सिलसिला होता है। करीब डेढ़ साल पहले जब शिंदे सरकार का गठन हुआ तो कोरोना महामारी के संकट से निकलकर राज्य को वापस अपनी ऊंचाई पर लाना था। उद्योग, व्यापार से लेकर रोजगार तक सभी को पटरी पर लाना था।

किंतु बीते दिनों में आंदोलनों की बढ़ती सूची और निवेश के कागजी आंकड़ों से अलग कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दावे के लिए समृद्धि महामार्ग जैसी पिछली सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं पूरी होने जा रही हैं। मुंबई की भी कुछ अधूरी परियोजनाओं को गति मिल चुकी है। पुणे और मुंबई मेट्रो का काम गति पकड़ चुका है। बावजूद इसके किसान से लेकर अलग-अलग समाज के आरक्षण के लिए आंदोलन कहीं न कहीं समाज में असंतोष की ओर इशारा कर रहे हैं। वर्ना इतनी बड़ी संख्या में देर-सबेर होते आंदोलनों में भीड़ नहीं जुटती। यदि रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं तो समाज का बड़ा वर्ग सड़कों पर नहीं उतरता है। दुर्भाग्य से समाज के अनेक बड़े तबके अपनी मांगों के लिए सड़क पर हैं। जिनका सीधा संबंध शिक्षा और रोजगार से है। 'थ्री ट्रिलियन' अर्थव्यवस्था का सपना देख रहा राज्य हमेशा ही निवेश की उर्वरक भूमि के रूप में पहचाना गया है। निजी क्षेत्र की अच्छी उपस्थिति के कारण अनेक औद्योगिक क्षेत्रों के आस-पास रहने वालों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार मिले हैं। या फिर उद्योगों के सहारे अपना कारोबार चलाने के लिए बल मिला है। किंतु बीते कई सालों से स्वरोजगार की मुश्किलों के चलते रोजगार के अवसरों की तलाश जोरों पर चल रही है। युवा वर्ग बेरोजगारी के संकट से बाहर आना चाहता है। उसे मौके नहीं मिल पा रहे हैं। जिसका कारण औद्योगिक क्षेत्र का समुचित विस्तार नहीं हो पाना है।

राज्य के अनेक भागों में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। किंतु उनमें उद्योग नहीं आ रहे हैं। कृषि क्षेत्र के लिए पूरक उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के नाम पर अनेक स्थानों पर जमीनें आवंटित की गई हैं, लेकिन वहां कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हो रहा है। छत्रपति संभाजीनगर, जालना, नांदेड़, धाराशिव, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, धुलिया, जलगांव, सोलापुर जैसे अनेक इलाके हैं, जहां अभी-भी एक बड़ी औद्योगिक परियोजना का इंतजार है। मुंबई, पुणे के क्षेत्र भरने के बावजूद अन्य इलाकों की ओर उद्यमियों के रुचि नहीं दिखाने के कारण और उसका समाधान नहीं ढूंढ़ा जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में आसमानी संकट से अधिक उपज का सही दाम नहीं मिलने का है। आयात-निर्यात की के झंझटों के बीच किसान को उसकी नियमित आय के लिए ठोस उपाय नहीं मिल पा रहा है। अनेक इलाकों में विकास के नाम पर अधिग्रहीत की जा रही कृषि भूमि से प्रभावित किसानों को मुआवजा तो मिल रहा है, लेकिन उनके भविष्य को नई दिशा देने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। साफ है कि लगातार बढ़ती अपेक्षाओं के आगे सरकार बौनी साबित हो रही है। दरअसल राजनीति के लिए अनेक पैंतरों को अपनाने की जरूरत सामान्य होती है। जिससे कुछ समय के लिए समाज का एक वर्ग संतुष्ट हो भी जाता है। मगर जब बात रोजी-रोटी के संघर्ष की आती है तो जमीन पर समस्याओं का निराकरण करना आवश्यक हो जाता है। महाराष्ट्र ने बीते दो दशक में राजनीतिक उठापटक काफी देखी है, लेकिन उसके अपेक्षित परिणाम सरकारें नहीं दे पा रही हैं। सत्ता की बागडोर को संभालने के बाद ठोस परिवर्तन दिखना आवश्यक होता है। मगर अनेक दावों के बावजूद सरकार बदलाव को प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध नहीं कर पा रही है।

समुद्र तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, डॉ बाबासाहब आंबेडकर का स्मारक, छत्रपति संभाजीनगर, धाराशिव जैसे शहरों के नाम जनभावनाओं का सम्मान तो हो सकते हैं, लेकिन उनसे जनआकांक्षाओं और जनसमस्याओं को किनारे नहीं किया जा सकता है। ऐसे में चौंकाने वाले चेहरों के नाम पर चर्चाएं तो बहुत हो सकती हैं, किंतु उनसे अपेक्षाएं पूरी होने की गारंटी भी मिलनी चाहिए। जैसी चुनाव के पहले देने का चलन आरंभ हुआ है। वर्तमान में महाराष्ट्र में अनेक समस्याएं और चिंताएं मुंह खोल कर खड़ी हैं। उनका समाधान आम जनता चाहती है। आंदोलन और विरोध जन आक्रोश के प्रतीक हैं। उनसे स्पष्ट संदेश लेने की आवश्यकता है। नए चेहरे के बाद नए लक्ष्यों को हासिल करने की भी आवश्यकता है। तभी नई पहचान सरकार के कामों की पहचान बन सकती है।

बस्तर में भूमकाल आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी!

कांकेर के चिलपरस में आदिवासियों ने कहा- धधक रही आग

कांकेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाने आंदोलन कर रहे हैं। पूरे बस्तर में 30 से 35 जगहों पर आदिवासी आंदोलन पर बैठे हुए हैं। कांकेर के चिलपरस में आदिवासियों के आंदोलन को एक साल हो गया है। आंदोलन के एक साल पूरे होने पर चिलपरस में बड़ी संख्या में आदिवासी इकट्ठा हुए। श्वङ्गङ्क भारत भी कांकेर पहुंचा और आदिवासियों से बात की।

चिलपरस आंदोलन में बैठे आदिवासियों ने बताया बिना ग्राम सभा की अनुमति के कैंप खोले गए। कोयलीबेड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इसीलिए इस क्षेत्र में पेसा एक्ट लागू है। पेसा एक्ट में गांव में जो भी काम होता है चाहे शासन का हो या किसी और का जब तक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक गांव में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन बिना किसी सूचना के चुपचाप कैंप लगा दिया जा रहा है। यह क्षेत्र अंदरुनी होने के चलते स्वास्थ्य और शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। इसको लेकर कई बार कोयलीबेड़ा ब्लाक मुख्यालय में प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बदले कैंप खोल दिए गए।

आंदोलनकारी मैनी कचलाम ने कहा बेचाघाट में तीन मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जिनमें बेचाघाट में प्रस्तावित पुलिया, सितरम में पर्यटन केंद्र और बेचाघाट में बीएसएफ कैंप। उसी तरह चिलपरस में भी रोड चौड़ीकरण, बीएसएफ को लेकर एक साल से आंदलोन कर रहे हैं। पूरे बस्तर में 30 से 35 जगहों पर आंदोलन चल रहा है।

आदिवासी समाज के नेता सहदेव उसेंडी ने बताया चिलपरस में एक साल से आंदोलन कर रहे हैं। जल जंगल और जमीन की लड़ाई है। आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि जल और जंगल खत्म हो जाएगा तो आदिवासी कहां जाएंगे। कम से कम सरकार को पहल करते हुए जल जंगल और जमीन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन सरकार इस मामले में कोई बात नहीं करती।

आदिवासी समाज के नेता सहदेव उसेंडी ने कहा पांचवीं अनुसूची क्षेत्र है। बिना ग्राम सभा के कैंप और सड़कों का काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी है लेकिन शासन की तरफ से इस तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है। ग्राम सभा की अनुमित लेकर कैंप बनाए, सड़क बनाएं कोई परेशानी नहीं है। सर्व आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष सूरजु टेकाम ने आरोप लगाया कि आदिवासियों की सुरक्षा के नाम पर अंदरूनी इलाको में सुरक्षा बलों का कैंप खोला जा रहा है। आदिवासियों को फर्जी मामलों में नक्सली बताकर जेल भेजा जा रहा है। जंगलों में बसे गांवों के आदिवासियों को फर्जी तरीके से मुठभेड़ कर उन पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। टेकाम ने कहा बस्तर में 1910 में भी आंदोलन चला। बड़ा विद्रोह हुआ। उस समय आदिवासियों ने जल जंगल जमीन को बचाने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। लगभग 45 दिनों तक आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई और अंग्रेज भागने के लिए मजबूर हो गए। अब 1947 की आजादी के बाद एक बार फिर आदिवासियों को जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आदिवासी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र की तरफ से लाए गए यूसीसी और वन संरक्षण कानून लाया गया।

सूरजु टेकाम उपाध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज ने कहा आंदोलन के कई रूप होते हैं। अब तक जो आंदोलन हो रहा है वो शांतिपूर्ण आंदोलन है। लेकिन इसका दूसरा रूप भी यहां के आदिवासी दिखा सकते हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। यहां एक आग धधक रही है। नई पौधे उग रहे हैं। आने वाली पीढ़ी दूसरे भूमकाल आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रही है।

बीजापुर के सिलगेर, भैरमगढ़, कांकेर के अंतागढ़, कोयलीबेड़ा, राजनांदगांव, मोहला मानपुर से बड़ी संख्या में आदिवासी शिरकत कर रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी वे आंदोलन जारी रखेंगे।

धमतरी नगर निगम टैक्स वसूली में फिर फिसड्डी

आखिर के तीन महीने कर्मचारियों को दी बड़ी चेतावनी

धमतरी। नगर निगम टैक्स वसूली के मामले में पीछे रहने का अपना रिकॉर्ड कायम रखे हुए हैं। वित्तीय वर्ष खत्म होने में करीब तीन माह ही बाकी है। लेकिन अभी भी लगभग 47 फीसदी कर वसूली नहीं हो पाई है। कर वसूली के लिए बीच-बीच में अभियान जरूर चलाए गए। लेकिन ज्यादा आउटपुट हाथ नहीं आया। अभी भी धमतरी नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर, दुकानों का किराया, निर्यात कर, यूजर चार्ज जैसे विषयों में लंबा चौड़ा किराया लेना बाकी है।

जहां तक आंकड़ों की बात करें तो 795 करोड़ रुपए की वसूली की जानी है। अब तक सिर्फ 349 करोड़ रुपए ही वसूला जा चुका है। अब नगर निगम के वसूली परफॉर्मेंस को देखते हुए यह मानना मुश्किल है कि बचे हुए समय में बाकी रकम की वसूली हो पाएगी। इस मामले में नगर निगम का खराब प्रबंधन तो कारण है ही, आम लोगों का टैक्स देने में रुचि नहीं लेना या उससे बचने की कोशिश में रहना यह भी एक बड़ा कारण है।

टैक्स वसूली को 100 फीसदी पूरा करने के लिए नगर निगम की तत्परता के साथ-साथ जनता की जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। इस मामले में नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर पीसी सार्वा ने कहा कि आचार संहिता और चुनाव ड्यूटी के चलते अधिकारी कर्मचारी व्यस्त थे। सभी को सख्त निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द टैक्स वसूली करें। निगम ने वूसली नहीं करने पर कर्मचारियों के वेतन से कटौती करने की चेतावनी भी दी है। नगर निगम के उपायुक्त ने अपील किया है कि जितने भी कर धारक हैं वह समय रहते अपना टैक्स अदा कर दें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे।

छत्तीसगढ़ में डायरिया का कहर

एक ही परिवार के 4 लोग पाए गए संक्रमित, अस्पाल में भर्ती

■ **3 दर्जन से अधिक लोगों का घर में चल रहा इलाज**

दुर्ग। मौसम के तापमान में गिरावट के साथ ही दुर्ग जिले में डायरिया फिर से पैर पसारने लगा है। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में डायरिया ने पैर पसार लिया है। यहां एक ही परिवार के 4 लोग डायरिया से संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं इसके अलावा मोहल्ले के 3 दर्जन से ज्यादा लोग घरों में ही रहकर इलाज करवा रहे हैं। गौतम नगर में 2 माह में अब तक 50 से ज्यादा लोग डायरिया से संक्रमित हो चुके हैं।

बता दें कि, हर साल ठंड के समय दुर्ग जिला डेंगू, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियों से प्रभावित होता रहा है। वहीं डायरिया के मामले में संवेदनशील रहे भिलाई के गौतम नगर में उल्टी-दस्त से 50 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। डायरिया के बड़ी संख्या में संक्रमित पाए जाने के बाद जिला स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग, भिलाई निगम के स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मौके पर तैनात कर दी गई है और प्रभावितों की जांच की जा रही है। वर्तमान में 7 लोगों का उपचार सुपेला सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जिनकी स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है।

दरअसल जिला स्वास्थ्य महकमा ने डेंगू, मलेरिया, डायरिया तथा पीलिया के मामले में भिलाई का कैंप और खुर्सीपार को सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर घोषित कर रखा है। डायरिया के मरीज मिलने के बाद अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर सर्वे कर रही है। मितानिन द्वारा घरों में सर्वे के दौरान लोगों को उल्टी-दस्त से पीड़ित की संख्या अधिक पाई गई। तब स्वास्थ्य महकमे को जानकारी दी जा रही है, आसपास के घरों में क्लोरिन टेबलेट बांटी जा रही है। उल्टी-दस्त की शिकायत पर फौरन भिलाई निगम के स्वास्थ्य अमले को प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है। यह सभी जल जनित रोग हैं, इसलिए साफ पानी का इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए।

अपनी ही जमीन के लिए सरकारी दफ्तर की ठोकरें खा रही दिव्यांग महिला

कौन इस गड़बड़ी का जिम्मेदार? आखिर कब मिलेगा न्याय

महासमुंद। जमीन संबंधी विवाद से परेशान होकर एक दिव्यांग महिला महासमुंद जिले के ग्राम बिरकोनी में अपनी बहन के घर के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गई है। दिव्यांग महिला के आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है। गोबरा नवापारा की दिव्यांग महिला तुलसी साहू अपनी छोटी बहन राजकुमारी साहू के घर बिरकोनी महासमुंद में रहती है। 60 प्रतिशत दिव्यांग तुलसी ने गरियाबंद जिले के पीपरखेड़ी में 7 साल पहले 0.35 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। रजिस्ट्री स्टाम्प, बी1, नक्शा, भुईया रिकार्ड में 0.35 हेक्टेयर जमीन उनके नाम पर दर्ज है। तुलसी अब उस जमीन को बेचकर महासमुंद में जमीन लेना चाह रही है। जिसके लिए तुलसी ने पटवारी से नकल मांगा तो पटवारी ने इनकी जमीन 0.31 हेक्टेयर हो?ने का हवाला देते हुए उतने ही जमीन का नकल देने की बात कह रहा है।

तुलसी ने इसकी शिकायत गरियाबंद कलेक्टर से जन चौपाल में की। लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद तुलसी ने इसकी शिकायत महासमुंद कलेक्टर से की तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो तुलसी ने गरियाबंद और महासमुंद कलेक्टर कार्यालय में आमरण अनशन की सूचना देकर 15 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठ गई हैं।

दिव्यांग तुलसी साहू और उनके परिजन का कहना है कि जब सारे रिकार्ड में हमारी जमीन 0 135 हेक्टेयर है तो हम नकल 0.31 हेक्टेयर का क्यों लें, जब तक हमारे प्रकरण का समाधान नहीं निकलता आमरण अनशन पर बैठी रहूंगी। वहीं महासमुंद एसडीएम का कहना है कि मामला गरियाबंद का है। मैंने जानकारी ली तो पता चला कि जमीन वास्तव में 0.31 हेक्टेयर है, बेचने वाले ने बढ़ा कर बेचा है। गरियाबंद राजस्व अधिकारी से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में 20 को होगा मतदान

■ **संघ अध्यक्ष के लिए अरुण कुमार दास, सपन कुमार देवांगन और राकेश दास ने नामांकन दाखिल किया**

जगदलपुर। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में 20 दिसंबर को मतदान होना है, इसके लिए नामांकन की प्रकिया पूरी कर ली गई है। संघ अध्यक्ष के लिए अरुण कुमार दास, सपन कुमार देवांगन और राकेश दास ने नामांकन दाखिल किया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए तीन तो कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए दो नामांकन दाखिल हुए है जबकि ग्रंथपाल, क्रीड़ा सचिव, सहसचिव व कार्यकारिणी सदस्य के लिए भी निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है। 20 दिसंबर को मतदान और उसके बाद मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे। अधिवक्ता संघ चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 365 से अधिक मतदाता है।

जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए अरुण कुमार दास, सपन कुमार देवांगन, राकेश दास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए अजीम मोहम्मद, नितेंद्र कौशिक, पवन कुमार राजपूत, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए हेलिना गिरिधरन, सुकांति पाटले, सचिव पद के लिए लिखेश्वर जोशी, अजय श्रीवास्तव, सहसचिव पद के लिए एक मात्र नाम संतोष चौधरी, कोषाध्यक्ष पद के लिए दीनबंधु रथ और निर्मल कुमार सोनी, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव पद के लिए भी एक मात्र नाम संजय कुमार जायसवाल, ग्रंथपाल के पद के लिए विजय प्रकाश दास और मनबोध राम बघेल ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं कार्यकारिणी सदस्य (आरक्षित महिला) पद के लिए एक मात्र नाम संगीता बृज फर्नांडिस एवं कार्यकारिणी सदस्य के लिए देववृत साहा, पूनम सोनी, ऋषि तिवारी, श्रवण कुमार शुक्ला, मौसम लुनावत ने नामांकन दाखिल किया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पत्थलगांव को नया जिला बनाने अडिग हूं : गोमती साय

पत्थलगांव। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार विधायक गोमती साय पत्थलगांव पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह लड्डू और मिठाइयों से तौलकर गोमती साय का स्वागत किया। इस दौरान पत्थलगांव को जिला बनाने के लिए विधायक गोमती साय का साफ कहना है कि अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है। अब पत्थलगांव को नया जिला बनाने के लिए उन्हें जितनी भी ताकत लगानी पड़ेगी, इस काम के लिए वे अडिग हैं। पत्थलगांव में कांग्रेस के वयोवृद्ध विधायक रामपुकार सिंह को गोमती साय ने चुनाव में बेहद रोमांचक मुकाबले में पराजित किया है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित विधायक गोमती साय का विजय जुलूस निकाल कर खुशियों का इजहार किया। नवनिर्वाचित विधायक गोमती साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में महिलाओं की बेहद अहम भूमिका है। इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार सुदृढ़ पहल करेगी।

किसान के खलिहान में रखे धान जलकर हुआ खाक

कोंड़ागांव। केशकाल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बिंझे के आश्रित ग्राम चिखलाडीही में बीती रात किसान हीरूराम के घर के पीछे रखे धान के कूप में आग लगने के कारण उसके 20 एकड़ खेत में लगे दो दो हजार भारा धान पूरी तरह जलकर राख हो गया है। जिसके कारण किसान हीरूराम के साल भर की मेहनत पूरी तरह चौपट हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिखलाडीही पारा निवासी किसान हीरू राम ने अपने घर के खलियान में धान रखा था, अज्ञात कारणों के चलते उसके धान में अचानक आग लग गई, लेकिन घर के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। सुबह 6 बजे जब घर के लोगों ने उठकर देखा तो पूरा धान जलकर राख हो चुका था। कुछ हिस्से को घर के लोगों ने पानी से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना पर पटवारी मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया। पटवारी पंचनामा के अनुसार उक्त किसान के पास कुल दो हजार भारा धान रखा हुआ ऐसे में 31 रुपए प्रति किलो की दर से 03 लाख दस हजार रुपए का नुकसान उक्त किसान को हुआ है।

राजिम नगर पंचायत में करोड़ों का घोटाला

राजिम। राजिम में करोड़ों रुपयों के भष्टाचार का मामला सामने आया है। राजिम के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता विनित पारख ने बड़ा खुलासा करते हुए नगर पंचायत राजिम में करोड़ो रूपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। विनित के मुताबिक उनके पास इससे जुड़े साक्ष्य भी मौजूद है। आरटीआई कार्यकर्ता विनित पारख ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नगर पंचायत राजिम में शासन ने कुल 43 प्लेसमेंट कर्मचारीयो की स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन यहां कई सालो से 10 अतिरिक्त लोगो का अर्थात कुल 53 लोगो का भुगतान हर माह किया जा रहा है, जबकि संचालक नगरीय प्रशासन के आदेशानुसार स्वीकृत लोगो से एक भी अधिक कर्मचारी के भुगतान किए जाने पर उसकी पूरी रिकवरी नगर पंचायत के सीएमओ के तनख्वाह से की जानी है। बावजूद उसके नगर पंचायत राजिम में वर्षो से एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। विनित पारख ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार नगर पंचायत में 20 लाख रूपये से अधिक के कार्यों पर ई टेंडर कराने का प्रावधान है।

कड़ाके की ठंड के बीच स्कूलों के समय में बदलाव

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है पेंड्रा रोड मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी अनुसार न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री है और अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरने की संभावना है। वहीं जबरदस्त कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच कलेक्टर ने स्कूल संचालन के समय में बदलाव का आदेश दिया है। शीत लहर और तेज ठंड को देखते हुए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। एक पाली में लगने वाले स्कूलों का समय सुबह 10.00 बजे से लेकर 4.00 बजे तक कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दो पारियों में लगने वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में सुबह 7.30 से 11.30 बजे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी क्लास को 12.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक संचालित किया जाएगा। वहीं सप्ताह में एक दिन शनिवार को सुबह 8.00 बजे से लेकर दोपहर 12.00 तक कक्षाएं संचालन करने का आदेश जारी किया गया है।

सड़क पर खड़े चार युवक को कार ने रौंदा, एक की मौत

बिलासपुर। बिलासा ताल के पास सड़क पर रविवार की देर रात चार युवक बातचीत करते हुए खड़े थे कि नशे में धुत कार चालक ने उन्हें रौंद दिया जिससे घटनास्थल पर ही एक युवक की मौत हो गई हीं तीन गंभीर युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोनी पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासा ताल के पास सड़क पर रविवार की देर रात 4 युवक खड़े थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने सभी को टक्कर मार दी जिससे घटनास्थल पर ही एक युवक की मौत हो गई वहीं तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया जिससे काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। घटना की सूचना मिलते ही कोनी पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे को समझाया जिसके बाद यातायात फिर से सामान्य हो पाया। नशे में धुत कार चालक की ग्रामीणजनों ने जमकर धुनाई भी की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

ओपी जिंदल विवि में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन-2023 का आयोजन 19 व 20 को

रायगढ़। ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन-2023 (सॉफ्टवेयर एडिशन) के ग्रैंड फिनाले का आयोजन 19-20 दिसंबर 2023 के दौरान किया जायेगा, जिसमे पूरे भारत से कुल 26 टीम्स और 200 से अधिक प्रतियोगी शामिल होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ आर. डी. पाटीदार ने बताया की 19 व 20 दिसंबर को स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के छठे संस्करण के ग्रैंड फिनाले के लिए ओपीजेयू नोडल केंद्र के रूप में चुना गया है। ओपीजेयू को नोडल केंद्र के रूप में चयनित करने के लिए कुछ दिनों पूर्व सम्बंधित अधिकारीयों ने कैंपस विजिट किया और विश्वविद्यालय

में उपलब्ध पर्याप्त सुविधाओं के आधार पर नोडल केंद्र के रूप में इसका चयन किया। यह आयोजन शिक्षा मंत्रालय इनोवेशन सेल की एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जो छात्रों को सरकारी निकायों, मंत्रालयों, विभागों, उद्योगों और संगठनों द्वारा उत्पन्न वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस वर्ष के स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में 44,000 से अधिक टीमों द्वारा 50,000 से अधिक विचार प्रस्तुत किए गए है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन-ग्रैंड फिनाले के दौरान, छात्र टीम चयनित प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कार्यशील समाधान तैयार करने के लिए सलाहकारों और उद्योग/मंत्रालय प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में चौबीसों घंटे काम करती है।

ओपीजेयू में यह प्रतियोगिता 19 दिसंबर को सुबह 9 बजे शुरू होगी और 20 दिसंबर को रात 9 बजे समाप्त होगी। सभी प्रतियोगी दल दो दिनों तक अनवरत 15 जजों एवं मेंटर्स के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतियोगिता के लिए पूरे भारत में कुल 47 नोडल केंद्र हैं और ओपीजेयू उनमें से एक है। इस प्रतियोगिता में ओपीजेयू से चार टीम्स को चुना गया है और वे विभिन्न नोडल सेंटर्स में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ की चांसलर श्रीमती शालू जिंदल ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन-2023 (सॉफ्टवेयर एडिशन) के ग्रैंड फिनाले के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ आर. डी. पाटीदार एवं सभी सदस्यों को बधाई दिया और प्रतियोगिता में शामिल हो रहे सभी प्रतियोगियों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त किया।

नक्सलियों ने पंप हाउस को किया आग के हवाले

दंतेवाड़ा। जिले के बचेली थाना क्षेत्र अंतर्गत आकाशनगर स्थित एनमडीसी के पंप हाउस को आग के हवाले कर दिया है। मौके पर नक्सलियों ने बड़ी संख्या में भारत बंद के पर्चे भी फेंके है। मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने रविवार देर रात में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी जानकारी सोमवार सुबह एनएमडीसी प्रबंधन को काम प्रभावित होने से हुई। गौरतलब है कि नक्सली भारत बंद को लेकर आक्रामक नजर आ रहे है। विदित हो कि हफ्ते भर में नक्सली बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में जवानों को निशाना बनाने में कामयाब हुए हैं। इसी कड़ी में नक्सलियों ने आकाशनगर स्थित एनमडीसी के पंप हाउस को आगे के हवाले कर दिया है। वहीं कुछ दिन पूर्व दंतेवाड़ा जिले के भांसी क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगी वाहनों में आगजनी की थी। बचेली में आगजनी के साथ नक्सलियों ने अरनपुर- जगरगुंडा मार्ग पर कामरगुड़ा के पास भी बैनर पोस्टर लगा भारत बंद का आह्वान किया है।

हत्या, आगजनी, विस्फोट में शामिल 1 नक्सली गिरफ्तार

नारायणपुर। जिले मेंचलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत छोटेडोंगर से डीआरजी, जिला पुलिस बल एवं आईटीबीपी 29वीं वाहिनी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु ग्राम चमेली, बाहकेर, रोहताड़ एवं तुरूषमेटा की ओर सर्चिंग में रवाना हुई थी। इसी दौरान वाहनों में आगजनी व मजदूरों के साथ मारपीट कर मुंशी की हत्या की वारदात में शामिल एक नक्सली मिलिशिया सदस्य मनदेर दर्रो को ग्राम तुरूषमेटा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली मिलिशिया सदस्य मनदेर दर्रो 23 सितंबर 2021 को ग्राम मढ़ोनार के पास सड़क निर्माण में लगे वाहनों में आगजनी व मजदूरों के साथ मारपीट कर मुंशी की हत्या की वारदात में शामिल रहा है। इसके अलावा 13 दिसंबर 2023 को अमदई घाटी में सुरक्षा बल पर किए गए आईईडी विस्फोट की वारदात में भी शामिल रहा। उक्त दोनों वारदातों को लेकर छोटेडोंगर थाने में पृथक-पृथक अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था।

अनुसूचित जनजाति का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता : साय

आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह एवं आमसभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री, गरीबों को आवास मुहैय्या कराने का वादा हमने पूरा किया

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ द्वारा आयोजित आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह एवं आमसभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत गजमाला एवं पगड़ी पहनाकर पारंपरिक आदिवासी स्वागत गीत से किया गया।

इस अवसर पर समारोह को सम्बोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि आज 18 दिसंबर का दिन है। आप सभी को बाबा गुरु घासीदास जयंती की हार्दिक बधाई। परमपूज्य बाबा गुरु घासीदास जी ने समाज को मनखे मनखे एक समान का संदेश देकर हम सभी को नया रास्ता दिखाया। आज हमारे समाज के लिए सौभाग्य की बात है कि जिस छत्तीसगढ़ में करीब 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी है और जहां सबकी अपेक्षा थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने, हमारे आदिवासी समाज की इस उम्मीद को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरा किया है।

श्री साय ने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण पूरी दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है। आज देश के सर्वोच्च महामहिम राष्ट्रपति के पद पर हमारे आदिवासी समाज की श्रीमती द्रोपदी मुर्मू जी विराजमान है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, ताकि यहां के अनुसूचित जनजाति के लोगों का समुचित सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके। अनुसूचित जनजाति का सर्वांगीण विकास हो सके इसलिए उन्होंने भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण विभाग का गठन भी किया। अनुसूचित जनजाति समुदाय की सबसे ज्यादा चिंता हमारी सरकार करती है।

श्री साय ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास का संकल्प लेकर मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता से जो भी वादा हमने किया है, उसे पूरा करने की जवाबदारी हमारी है। हमारी सरकार ने ही महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष माताओं-बहनों को 12 हजार रुपए और किसानों के हित में 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की घोषणा सहित प्रत्येक वर्ग के हित में घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि गरीबों को आवास मुहैय्या कराएंगे, हमने इसे पूरा किया। हमने 13 दिसम्बर को शपथ ग्रहण किया और 14 दिसंबर को सबसे पहले केबिनेट में 18 लाख हितग्राहियो को आवास देने का निर्णय लिया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, विधायक श्री केदार कश्यप, विधायक श्री कवासी लखमा सहित आदिवासी समुदाय के अन्य विधायक, एवं अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के प्रांताध्यक्ष आर एन ध्रुव सहित आदिवासी समुदाय के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

शासकीय सेवक संघ ने सीएम को सौंपा मांग पत्र

पंडित दिनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आदिवासी समाज का सम्मान समारोह हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत बीजेपी व कांग्रेस के कई विधायक शामिल हुए। इस दौरान आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने सीएम साय को मांग पत्र सौंपा। सीएम से आदिवासियों के लिए विशेष भारती अभियान चलने, पदोन्नति में आरक्षण लाभ दिलाने, आदिवासी के फर्जी प्रमाणपत्र पर कर रहे नौकरी को निरस्त करने, स्थानीय भर्ती की शुरुआत करने, 33% आरक्षण के अनुरूप प्रदेश में 11 कलेक्टर और 11 एसपी नियुक्त किए जाने की मांग की गई है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम साय ने कहा, आज जनजातीय शासकीय सेवक संघ की ओर से विधानसभा चुनाव 2023 में अनुसूचित जनजाति वर्ग से जितने विधायक निर्वाचित हुए हैं उनके सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। यहां अनुसूचित जनजाति के बहुत से विधायक शामिल हुए, जहां सभी का सम्मान व स्वागत किया गया। बहुत से अनुसूचित जनजाति समाज के विधायक निर्वाचित हुए हैं, उनका सम्मान किया है। उचित मांग होगा जो भी पूरा हो सकता है वह सब पूरा करेंगे।

आदिवासी मुख्यमंत्री का सपना प्रधानमंत्री ने साकार किया : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान में आयोजित समारोह में उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज 18 दिसंबर है,परमपूज्य बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर उन्हे नमन करता हूं। उन्होंने समाज को मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया।आज हमारे समाज के लिए सौभाग्य की बात है कि जिस छत्तीसगढ़ में करीब 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी है, वहां सबकी अपेक्षा थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने और वह अपेक्षा साकार हो गई।

हमारे आदिवासी समाज की उम्मीद को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरा किया है। आज पूरी दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है, हमारे प्रधानमंत्री के कारण। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर हमारे समाज की महिला द्रोपदी मुर्मू जी विराजमान है।छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ताकि यहां के अनुसूचित जनजाति के लोगों का समुचित विकास हो सके, आर्थिक विकास हो सके।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि अनुसूचित जनजाति का सर्वांगीण विकास हो सके इसलिए उन्होंने भारत सरकार में पहली बार आदिम

जाति कल्याण विभाग का गठन भी किया। आदिवासी समाज की सबसे ज्यादा चिंता मोदी जी की सरकार करती आ रही है। सबका साथ, सबका विकास के साथ मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता से जो भी वादा हमने किया है पूरे पूरा करने की जवाबदारी हमारी है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष माताओं बहनों को 12 हजार रुपए, किसानों के हित में 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की घोषणा समेत हर वर्ग के हित में घोषणाएं की।हमने वादा किया था कि गरीबों को आवास मुहैय्या कराएंगे इसे पूरा करते हुए पहली कैबिनेट बैठक में ही हमने 18 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का निर्णय लिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, विधायक श्री केदार कश्यप, श्री विक्रम उसेंडी, श्री कवासी लखमा, श्रीमती गोमती साय, श्री नीलकंठ टेकाम सहित अन्य विधायकगण और आदिवासी समाज के सदस्य उपस्थित हैं।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार से पार्टी के नेता नाराज हैं। वहीं सीटिंग विधायक के टिकट काटे जाने से विधायकों में काफी नाराजगी है। इस बीच पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और उससे जुड़े सभी प्रभार से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व विधायकों का दल दिल्ली गया था और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत की थी। अकलतरा के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और उससे जुड़े समस्त प्रभार से इस्तीफा दिया है। उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को इस्तीफा पत्र भेजा है। पत्र में चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस की हार से दुख होने के कारण इस्तीफा देने की बात कही है।

निर्धारित जगह के अलावा कहीं और मांस-मटन बेचा तो होगी कार्रवाई

रायपुर। राजधानी में अब कहीं भी मांस मटन बेचने वालों पर शख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित जगह के अलावा कहीं और मांस मटन बेची तो कार्रवाई की जाएगी। मांस ङ्क मटन को ढककर भी रखना जरूरी है। बता दें कि 18 दिसम्बर गुरू घासीदास जयंती, 19 दिसम्बर संत तारण तरण जयंती के अवसर पर रायपुर परिक्षेत्र में स्थित पशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। राजधानी में मांस- मटन विक्रय दुकानों को बंद रखने के आदेश नगर निगम प्रशासन ने जारी किया है।

छत्तीसगढ़ के तीरंदाजी खिलाड़ियों ने हासिल किया कास्यां पदक

रायपुर। गुजरात में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम प्रतियोगिता में सोमवार को छत्तीसगढ़ के तीरंदाजी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक पर कब्जा किया। यह पदक अंडर 17 वर्ग में छत्तीसगढ़ की ओर से खेल रहे जय साहू, तुलेश्वरी खुसरो, राधो करतम और पद्मा साहू ने दिलाया।

कैट सीजी चैप्टर की प्रादेशिक सभा व स्नेह सम्मेलन आज

रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कैट सी.जी. चैप्टर की प्रादेशिक सभा एवं स्नेह सम्मेलन दिनांक 19 दिसम्बर 2023 को वृन्दावन हाल, सिविल लाईन्स, रायपुर में सुबह 11.30 बजे से प्रारंभ होगी है। कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया की कैट प्रादेशिक सभा एवं स्नेह सम्मेलन दिनांक 19 दिसम्बर 2023 को वृन्दावन हाल, सिविल लाईन्स, रायपुर में सुबह 11.30 बजे से प्रारंभ होगी है। प्रादेशिक सभा एवं स्नेह सम्मेलन में कैट एवं युवा टीम के पदाधिकारी, सभी जिला ईकाइयों से एवं सभी व्यापारी संगठनो के पदाधिकारीगण शामिल होगें। प्रादेशिक सभा में प्रदेश के सभी जिला ईकाइयों का पुर्नगठन एवं विभिन्न विभागों के लिए समिति गठन पर सहमति बनी। एवं विभिन्न व्यापारिक मुद्दो सहित संगठन के विस्तार के पर भी चर्चा की जायेगी।

मिड डे मील का नाश्ता अब तक शुरू नहीं किया: चरणदास महंत

■ नक्सलियों पर क्या लगाम लगाएंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने साय सरकार के मंत्रिमंडल गठन पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए। सरकारी योजनाएं क्या शुरू करेंगे। साय ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और मिड डे मील में बच्चों को नाश्ता शुरू ना करने को लेकर भी भाजपा पर हमला बोला।

केंद्र सरकार के साथ मिलकर नक्सल घटनाओं पर लगाम लगाने के सवाल पर चरणदास महंत ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लपेटे में लिया। उन्होंने पहली कक्षा से आठवीं कक्षा के बच्चों को नाश्ता देने के वादे पर सवाल उठाया है। उनका कहना है नक्सल घटनाओं को रोकने में केंद्र सरकार का सहयोग तो रहता ही है। लेकिन इन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि केंद्र सरकार और हमारे सहयोग से पहली कक्षा से आठवीं कक्षा के बच्चों को नाश्ता देंगे। सरकार बने 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं पर बच्चों को नाश्ता नहीं मिला है। मिड डे मील के लिए पिछले कुछ सालों का लगभग 300 करोड़ केंद्र से आया नहीं है। चरणदास महंत ने कहा जब बच्चों की ही चिंता उन्होंने शुरू नहीं की है, मिड डे मील की चिंता नहीं, जो केंद्र सरकार पर आधारित है, तो नक्सल पर क्या चिंता करेंगे, यह सोचनीय है।

बस्तर में किसान की खुदकुशी के मामले में भी महंत ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। महंत ने कहा हमारी सरकार ने पिछले पांच सालों में किसान को पहली प्राथमिकता में रखा। उनको समृद्ध बनाने के लिए अनेक योजनाएं भी दीं। उनके मेहनत का दाम भी दिया। लेकिन नई सरकार बनते ही आदिवासी बहुल बस्तर में आत्महत्याएं होने लगी। नक्सली हमले भी बढ़ गए हैं, जो दुखद है। अब इनके कारण क्या होंगे, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन सुना है कि जिनकी मृत्यु हुई है, उन पर कर्ज था और कर्ज उगाही के लिए गए थे। कांग्रेस पार्टी की घोषणा में हमने पांच सालों में एक लाख करोड़ रुपये छूट देने या उनको फायदा देने का वचन दिया था। मगर उनको हमारी घोषणा पर विश्वास नहीं हुआ। बीजेपी की घोषणा पर उन्होंने विश्वास किया। मुझे ऐसा लगता है जो परिणाम आयेंगे, वो अच्छे नहीं होंगे, दुखद होंगे।

सुरक्षा में चूक मामला: राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने सभापति को लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने सोमवार को संसद में चूक मामले को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने संसद में दो लोगों द्वारा स्मोक बॉम जलाकर कार्यवाही बाधित करने वाली घटना के संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ओर से बयान जारी करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस पर चर्चा की मांग भी रखी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 13 दिसंबर 2023 को, एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जिसमें दो अनधिकृत व्यक्तियों ने लोकसभा कक्ष में घुसपैठ की। उन्होंने चल रहे सत्र के दौरान नारे लगाकर और स्मोक बॉम जलाकर कार्यवाही को बाधित किया। इस घटना से पहले दो अन्य प्रदर्शनकारी संसद भवन के बाहर प्रदर्शन में शामिल हो गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन और धुआं बम जलाकर अपनी शिकायतें व्यक्त कीं। स्थिति की गंभीरता और संसद की प्रतिष्ठित संस्था और उसके सदस्यों की सुरक्षा पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, मैं ईमानदारी से अनुरोध करती हूं कि गृह मंत्री इस मामले पर एक बयान जारी करें। जिसके बाद तत्काल इस संबंध में एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

लोगों की अपेक्षाओं को करेंगे पूरा, मंत्रिमंडल विस्तार को पार्टी और संगठन तय करेगा: केदार

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर भाजपा नेता और विधायक केदार कश्यप ने कहा, कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार में अधिकारी संलिप्त थे और कांग्रेस के मंत्री मुख्यमंत्री के इशारे पर काम कर रहे थे। लगातार हमारे आदिवासी समाज के साथ कांग्रेस के लोगों ने अत्याचार किया। पदोन्नति में आरक्षण को रोक दिया। आरक्षण को लेकर किस तरह से यहां पर नाटक किया गया मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

केदार कश्यप ने कहा, स्थानीय भर्ती परीक्षा में बस्तर और सरगुजा में पोस्ट को खत्म करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो हमारी अपेक्षा है मोदी जी की जो गारंटी है, उसे गारंटी के साथ हम जनता के साथ चलेंगे और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। आदिवासी समाज की ओर से आयोजित सम्मान कार्यक्रम को लेकर पूर्व मंत्री व विधायक केदार कश्यप ने कहा, आदिवासी समाज के जो कर्मचारी संगठन है उनके द्वारा सभी आदिवासी नवनिर्वाचित विधायकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री का यहां पर सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। निश्चित तौर से यह बड़े गौरव का विषय है।

केदार ने कहा, यदि आदिवासी मुख्यमंत्री किसी ने दिया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नकली आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया। वास्तविकता है यह सच है। उन्होंने कहा, विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। कल विधानसभा सत्र का पहला दिन है। सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। कल शपथ ग्रहण के बाद ही अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी।

मंत्रिमंडल के गठन को लेकर केदार कश्यप ने कहा, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। पार्टी और संगठन आगे तय करेगा। कांग्रेस ने जिनकी टिकट काटी थी वह सभी 22 विधायक पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस पर विधायक केदार ने तंज कसते हुए कहा, यह तो अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बता पाएंगे। शीर्ष नेतृत्व कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार किया। इस तरह से उन्होंने संगठन में रहते हुए भ्रष्टाचार किया। दावेदारों से विधायकों से जिस तरह से पैसे लेने का काम किया है उसके कारण से कांग्रेस के जो विधायक और उम्मीदवार पूर्व विधायक वह सारे के सारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ में जा रहे हैं।

प्रदेश में व्यापारियों के घर आईटी की दबिश तीन दिन में सीज किए 15 करोड़ नगद और 3 लॉकर

कागजात और कैश भी बरामद, 1300 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की आशंका

रायपुर। राजधानी में आयकर छापे के तीसरे दिन 7 ठिकानों पर चल रही कार्रवाई खत्म हो चुकी है। वहीं 43 ठिकानों पर अभी भी जांच जारी है। आयकर विभाग ने 3 बैंक लॉकर को सीज कर लिया है। बाकी बैंक लॉकर्स में भारी मात्रा में जमीन के कागजात, कैश समेत जेवर बरामद किया गया है। आयकर की छापेमारी में अब तक 15 करोड़ रुपये नगद बरामद किया गया है।

इसके अलावा जांच दायरे में आए 18 प्रतिष्ठानों के संचालकों में से 3 संचालकों ने कर चोरी करने को स्वीकारा है। आयकर विभाग की 10 सदस्यीय अहमदाबाद से आई साइबर टीमें डिलीट मैसेज रिकवर करने में जुटी है। सोमवार की सुबह तक कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है।

आयकर विभाग के सूत्रों से जानकारी मिली है कि अफसरो को आशंका है कि कारोबारियों ने पिछले तीन सालों में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेन-देन में गड़बड़ी कर टैक्स चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ये आकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। कारोबारियों ने कितने की टैक्स चोरी की है इसका सही आकलन जांच के बाद ही पता चलेगा। बताया जा रहा है कि दाल, और कोल्ड स्टोरेज का पूरा कारोबार कच्चे लेन-देन में होता रहा है।

बता दें कि राजधानी में समता शॉपिंग आर्केड, तेलघानी नाका चौक, सिलतरा, कुशालपुर में टीमों की जांच चल रही है। समता शॉपिंग आर्केड स्थित केके एग्रो ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, तेलघानी चौक स्थित दाल कारोबारी ङ्गस सूरज पल्सेस, सिलतरा स्थित राजेश्वरी कोल्ड स्टोरेज के ठिकानों पर रेड जारी है।

जल्द होगा मंत्रिमंडल का गठन, नए-पुराने चेहरों को मिलाकर बनेगा कैबिनेट : साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली से लौट आए हैं। दिल्ली से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर साय ने मंत्रिमंडल गठन और धान खरीदी के बारे में बताया। साय रविवार शाम को केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली गए थे।

विष्णुदेव साय ने बताया गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। चर्चाएं हुई है। बहुत जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। 19 दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र 3 दिनों तक 21 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सत्र के दौरान ही विष्णुदेव सरकार के मंत्री शपथ ले सकते हैं।

विष्णुदेव साय ने कहा मंत्रिमंडल में नए लोगों के साथ पुराने चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मुख्यमंत्री के साथ 13 मंत्री बन सकते हैं। इस समय मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। ऐसे में 10 नए मंत्री बनने हैं। सीएम साय ने नए चेहरों के साथ पुराने चेहरों को भी मंत्री बनाने की बात कही। नए चेहरों में ओपी चौधरी, गुरु खुशवंत साहेब का नाम शामिल है। महिलाओं में गोमती साय, रेणुका सिंह और लता उसेंडी के साथ ही पहली बार विधायक बनी भावना बोहरा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। पुराने चेहरों में बृजमोहन अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, केदार कश्यप, अजय चंद्राकर को मौका दिया जा सकता है।

नए कैबिनेट में दस और सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। संवैधानिक मापदंडों के मुताबिक, 90 सदस्यीय विधानसभा में सीएम सहित अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं।

धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ सीएम ने कहा कि मोदी जी की गारंटी के अनुसार ही 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी होगी। साथ ही 1 एकड़ में 21 क्विंटल की धान खरीदी का फायदा प्रदेश के किसानों को मिलेगा।

किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, मोदी की गारंटी पर रखें भरोसा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौटे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। जिसमें उन्होंने धान खरीदी समेत अन्य मुद्दों पर बयान दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने धान खरीदी को लेकर कहा, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, मोदी की गारंटी है। जितने में खरीदने की बात हुई है, उसी दाम पर किसानों से धान खरीदा जाएगा।

शीतकालीन सत्र आज से, केवल प्रवेश पत्र धारी ही करेंगे प्रवेश

रायपुर। चार दिन पहले लोकसभा सदन में युवकों के कूदकर धमाचौकड़ी मचाने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा प्रशासन ने भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। सत्र अवधि के दौरान केवल प्रवेश पत्र धारी लोगों को ही विधान सभा परिसर में प्रवेश की पात्रता रहेगी। प्रवेश पत्र धारी व्यक्तियों को अपने संस्थान का परिचय पत्र या आधार कार्ड रखना आनिवार्य होगा। छठवीं विधानसभा का प्रथम शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। सत्र के प्रथम दिवस सभा में विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। 20 दिसम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद का अभिभाषण होगा। विधान सभा परिसर एवं सभी दीर्घाओं में सुरक्षा कर्मियों द्वारा कड़ी नजर रखी जायेगी। केवल विधायकों को ही वीआईपी गेट तक जाने की अनुमति होगी। विधायकों के साथ आये कार्यकर्ता एवं उनके परिजनों के लिए विधान सभा परिसर स्थित प्रेक्षागृह में बड़ी की स्क्रीन लगाकर सदन की सीधी कार्यवाही देखने की व्यवस्था की गयी हैं। उनका प्रवेश गेट क्रमांक-1 से होगा। नवनिर्वाचित सदस्यों के स्वागत में विधान सभा परिसर को फूल मालाओं एवं रंगोली से सजाया जा रहा है। बरौंडा चौक का नये तरीके से सौन्दर्गीकरण और विधान सभा परिसर को लोककला एवं लोक संस्कृति युक्त पेंटिंग से सजाया जा रहा है।

भाजपा ने सेट कर लिया 2024 का फॉर्मूला?

अंकित सिंह

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुराने क्षत्रपों को खत्म करते हुए भाजपा ने अपनी जीत के बाद तीन नए चेहरों को आगे किया है और राज्य की कमान सौंपा है। मध्य प्रदेश में जहां भाजपा ने मोहन यादव पर दांव लगाया है तो वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को चुना गया है। हिंदी हार्ट लैंड के भले ही इन तीन राज्यों नतीजों के बाद भाजपा ने कदम उठाया है लेकिन कहीं ना कहीं उसके निशाने पर 2024 है। भाजपा ने कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 के लिए अपना फार्मूला तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा के पास कई बड़े चेहरे रहे हैं। हालांकि, उन सभी चेहरों को किनारे करते हुए तीन नए चेहरों को सामने लाना कहीं ना कहीं भाजपा की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े ताकतवर नेता रहे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल जैसे नेताओं का भी दबदबा माना जाता है। वहीं, छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह का दौर खत्म हो चुका जबकि राजस्थान में ताकत दिखाने के बावजूद भी वसुंधरा राजे की बात नहीं बन सकी। इसके साथ ही उनके युग का भी अंत हो गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिन चेहरों को भाजपा ने आगे किया है उनकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संघ पर आधारित रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अपनी मुख्य राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में जाति संबंधी एजेंडे को भी सावधानीपूर्वक साधा है। बीजेपी की रणनीति में आदिवासियों, पिछड़ों, ऊंची जातियों और दलितों तक पहुंचने का प्रयास किया गया। राजस्थान में भजनलाल को मुख्यमंत्री बनकर भाजपा ने 2024 के लिए ऊंची जाति को साधने का बड़ा मंच तैयार कर लिया है। ब्राह्मण भाजपा के कोर वाटर माने जाते हैं। राजस्थान में डिप्टी सीएम को लेकर जो जातीय संतुलन बनाया गया है उसमें राजघराने से आने वाली दिया कुमारी हैं जो राजपूत हैं। वहीं, प्रेमचंद बैरवा दलित परिवार से आते हैं। उनके जरिए भाजपा राजस्थान के साथ-साथ उत्तर भारत में दलितों को साधने की कोशिश की है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा दांव लगाया है। यहां भाजपा ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है भाजपा ने जहां ओबीसी समुदाय को आते है। इससे खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों को बड़ा संदेश दिया है। भाजपा ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि वह अगर बिहार और उत्तर प्रदेश से ऐसे राज्यों में आती है तो वह किसी यादव को मुख्यमंत्री बन सकती हैं। परिवारवाद उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इन दोनों ही राज्यों में 10 से 12त्न आबादी यादवों की है। वहीं हरियाणा में भी यादवों के वोट अच्छे कहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा दलित समुदाय से आते हैं जो उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं। दूसरे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण हैं और सवर्णों को साधने में कामयाब हो सकते हैं। विष्णु देव साय आदिवासी समाज को साधने की कोशिश में भाजपा की मदद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है। भाजपा ने यह जातीय समीकरण की राजनीति ऐसे समय पर की है जब देश में विपक्षी दलों की ओर से जाति आधारित जनगणना की मांग लगातार की जा रही है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल ओबीसी के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश में हैं। हिमाचल और कर्नाटक में सत्ता गंवाने के बाद भाजपा ने जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की है उससे मोदी की गारंटी वाला दांव भी चल गया है। ऐसे में बीजेपी इन चहरों के साथ-साथ मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं जिससे उसे 2024 में फायदा मिल सके।

चिदंबरम की खरी बात

उमेश चतुर्वेदी

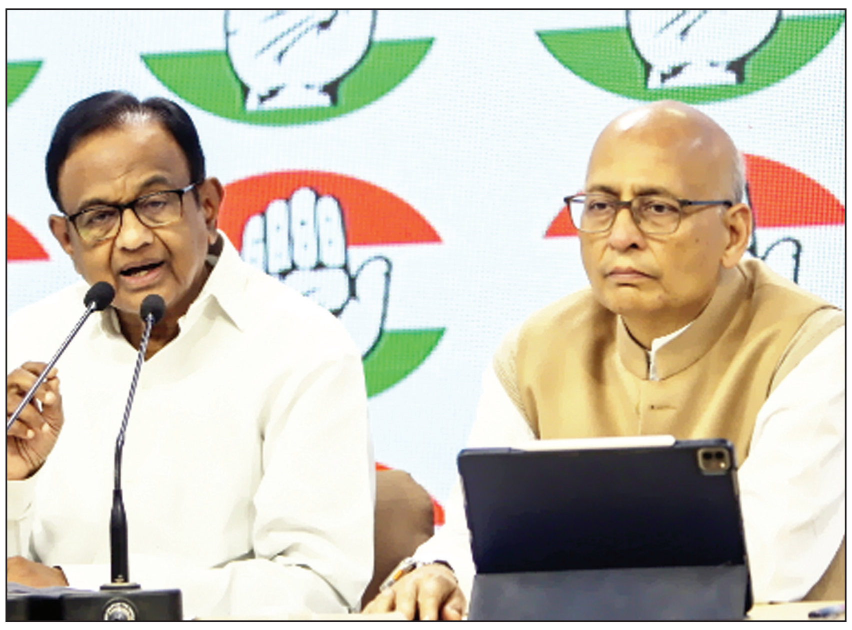

साल 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद हुए अधिकांश चुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन मजाल है कि उसके जिम्मेदार नेताओं ने कभी अपनी कमजोरी और गलतियों को स्वीकार किया हो। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का खुले तौर पर यह स्वीकार करना कि 2024 की चुनावी हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मामूली बात नहीं है। चिदंबरम की यह स्वीकारोक्ति इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस के जिम्मेदार नेता अपनी कमियों को कम से कम खुले तौर पर स्वीकार करने लगे हैं। ऐसे में उसके समर्थकों की ओर से यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या पार्टी अपनी असल कमियों की ओर ध्यान देगी और अपनी खोई हुई राजनीतिक प्रतिष्ठा हासिल करने की गंभीरता से कोशिश करेगी?

भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में नरेंद्र मोदी के उभार और उसके बुनियादी आधार को कांग्रेसी नेतृत्व ने कभी स्वीकार नहीं किया। आज का दलीय तंत्र जिस तरह विकसित हुआ है, उसमें नेतृत्व की बात को जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ता के लिए आंख मूंदकर भरोसा करना राजनीतिक मजबूरी है। कई बार जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और मंझला-निचला नेतृत्व तक आलाकमान की सोच से सहमत नहीं भी होता तो दलीय अनुशासन के नाम पर उसे आलाकमान की गलत और आसमानी सोच को ही स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे में कभी जमीनी राजनीतिक हकीकत का तथ्य कम से कम खुले तौर पर सामने आ ही नहीं पाता। इन्हीं संदर्भों में चिंदबरम की स्वीकारोक्ति गंभीर और महत्वपूर्ण हो जाती है।

याद कीजिए, साल 2013 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए कांग्रेस महाधिवेशन को। तब पार्टी केंद्र की सत्ता में थी। तब भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर कांग्रेस को चुनौती के रूप में नरेंद्र मोदी उभर रहे थे। इसे लेकर जब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर से पूछा गया तो उन्होंने मोदी की हैसियत और भावी चुनौती को ना सिर्फ नकार दिया, बल्कि उन्हें तालकटोरा के बाहर चाय का ठेला लगाने के लिए जगह देने का ऐलान कर दिया। लेकिन करीब छह महीने बाद हुए आम चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि विदेश सेवा के अधिकारी रहे मणिशंकर अय्यर की सोच और उनका आकलन कितने हवा हवाई थे।

लगातार दो संसदीय चुनावों में बड़ी हार के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने मोदी को चुनौती रूप में स्वीकार ही नहीं किया। भाजपा की जीत के खिलाफ कांग्रेस अपनी पारंपरिक और घिसीपिटी सोच के मुताबिक नैरेटिव गढ़ती रही। हिंदू बनाम मुसलमान का हौव्वा खड़ा करती रही, सांप्रदायिकता के पुराने सवाल को काठ की हांड़ी की तरह लगातार बार-बार सियासी आंच पर चढ़ाती रही। लेकिन वह जमीनी हकीकत से दूर भागती रही। इसका उसे कभी-कभी फायदा भी मिला। 2018 में उसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत मिली तो 2023 में कर्नाटक और हिमाचल में। इसके अलावा उसे कभी कोई बड़ी चुनावी जीत नहीं मिली। फिर भी कांग्रेस आलाकमान की केंद्रीय धुरी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई लड़ते रहे। उनके प्रवक्ता गलाफाड़ प्रतियोगितायों में शामिल होते हुए नैरेटिव के ही तर्क गढ़ते रहे।

दिल्ली के अभिजात्य इलाके में रहने वाले मीडिया कर्मियों, प्रोफेसरों और अतीत में सत्ता पोषित रहे बुद्धिजीवियों का एक वर्ग कांग्रेस आलाकमान के नैरेटिव केंद्रित विचारों को %भारत के विचार% के तौर पर प्रचारित करता रहा। कांग्रेसी इकोसिस्टम इस आभासी कोलाहल को भारतीय जनता का बुनियादी विचार मानता रहा। जमीनी राजनीतिक हकीकत से यह सोच जितनी दूर है, कांग्रेस के लिए चुनावी जीत उतनी ही दूर होती रही।

कांग्रेसी इकोसिस्टम चुनावी जीत को लेकर जो माहौल बनाता है, उसका केंद्र महानगरों के वे अभिजात्य इलाके होते हैं, जिसके हर पोर से समृद्धि चू रही होती है। लेकिन उसकी परिधि कुछ किलोमीटर तक ही होती है। इकोसिस्टम के इस छद्म वाले कोलाहल में कांग्रेसी तंत्र यह भूल जाता है कि भारत बहुत विशाल है। तमाम तरह की सोच, पहनावे और खानपान, माहौल और मिजाज वाला देश भला अभिजात्य की सोच को ही क्यों आत्मसात करेगा।

जबकि भारतीय जनता पार्टी इसके ठीक उलट जमीनी हकीकत की बुनियाद पर चुनाव लड़ती है। वह स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दों और सोच के लिहाज से रणनीति बनाती है, जनता को लुभाने की कोशिश करती है। बेशक उसकी यह रणनीति दक्षिण भारत के चार राज्यों आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में अपना असर नहीं दिखा पा रही है। फिर भी भाजपा ने अपनी उम्मीद नहीं खोई है। काशी को तमिलनाडु से जोड़ने जैसे विचार स्थानीयता की बुनियाद पर अपने सियासी पांव बढ़ाने की इसी सोच और कोशिश का नतीजा है। फिर भी वह अपना हर चुनाव युद्धस्तर पर लड़ती है। शायद यही वजह है कि अब चिदंबरम भी स्वीकार करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना हर चुनाव उसे आखिरी मानकर लड़ती है।

कांग्रेसी इकोसिस्टम के कोलाहल से उपजा विजय का छद्म कांग्रेसी नेतृत्व की दृष्टि को किस कदर कमजोर कर देता है, इसका उदाहरण बीते विधानसभा चुनाव हैं। इसी कोलाहल के चलते पार्टी और उसका आलाकमान इतने अहंकार में रहा कि उसने उस इंडी गठबंधन के दलों के साथ प्रतीकात्मक ही सही, सीटों का बंटवारा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसका अगुआ होने का वह खुद को स्वाभाविक दावेदार मानती है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में समाजवादी पार्टी समेत दूसरे दलों से उसका प्रतीकात्मक गठबंधन चुनाव के आखिरी दौर तक अनिर्णय की स्थिति में रहने वाले मतदाताओं के एक हिस्से को लुभा सकता था। लेकिन जब चुनाव नतीजे पक्ष में नहीं आए तो पार्टी को शायद अपनी भूल का अहसास हुआ और इंडी गठबंधन की फौरन बैठक बुला डाली। यह बात और है कि तब ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे अपने-अपने क्षेत्रों के कद्दावर नेताओं ने कांग्रेस को ही एक तरह से औकात बता दी और बैठक को 19 दिसंबर तक के लिए टालना पड़ा।

चिदंबरम ने यह भी स्वीकार किया है कि विपक्ष समेत कांग्रेस को बीजेपी की ताकत को समझना होगा। उसको उसी की भाषा में मुद्दों की बुनियाद पर आक्रामक जवाब देना होगा। भाजपा की ही तरह रणनीतिक तौर पर चुनावी मैदान में उतरना होगा। पूरी तैयारी करनी होगी। चिदंबरम की इस स्वीकारोक्ति का एक मतलब यह भी है कि कांग्रेस को अब यह मानकर चलने वाली सोच से आगे बढ़ना होगा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ देश की जनता उठ खड़ी होगी और उसे जिता देगी। कांग्रेस को यह भी मानना होगा कि नरेंद्र मोदी की भाजपा अतीत की भाजपा से कहीं आगे निकल गई है।

सांप्रदायिकता के ही इर्द-गिर्द उसकी ताकत को बांधने या आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या कांग्रेस अपने इस अनुभवी नेता की सोच के अनुरूप आगे बढ़ने और हकीकत के कठोर धरातल पर असल मुद्दों पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी?

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगचूडामण्युपनिषद् (भाग-15)

गतांक से आगे...

विश्व स्थूल का नित्य भोग करने वाला है, तैजस एकान्त का भोग करने वाला है, प्राज्ञ आनन्द का भोगने वाला है और सबका साक्षी (आत्मा) इससे परे कहा जाता है। सर्वव्यापी प्रणव (परमात्मा) जीवों की सभी आनन्दमय अवस्थाओं के भोग के समय अधोमुख अर्थात् उदासीन होकर रहता है।

(प्रणव कार में निहित) तीन अक्षर अ कार, उ कार एवं म कार तीन वेद, तीन लोक, तीन गुण, तीन अक्षर और तीन स्वर के रूप में प्रणव (ओंकार ही) प्रकाशमान है। अ कार समस्त जीवधारियों के जाग्रत अवस्था में नेत्रों में निवास करता है, सोते समय उ कार कण्ठ में निवास करता है और म कार सुषुप्ति अवस्था में हृदय प्रदेश में निवास करता है।

यह स्थूल विराट् विश्व अ कार ही है, सूक्ष्म तेजस्वी हिरण्यगर्भ के रूप में उ कार कहा जाता है और म कार अव्याकृत (अप्रकट) कारण प्राज्ञ कहा जाता है। अ कार की प्रकृति राजसी, वर्ण लाल है, उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहा गया है। उ कार की प्रकृति सात्त्विक, वर्ण श्वेत है, उसे पालनकर्त्ता विष्णु कहा गया है। म कार की प्रकृति तामस, वर्ण कृष्ण है, उसे संहारकर्त्ता रुद्र कहा गया है, इस तरह ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति का कारण प्रणव (?) ही कहा गया है। प्रणव ही सबका अनादि कारण परतत्त्व है। अ कार में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा समाहित हैं, उकार में विष्णु समाहित हैं तथा मकार में रुद्र समाहित हैं। एकमात्र प्रणव ही (सर्वत्र) प्रकाशमान रहता है। यह प्रणव ज्ञानी मनुष्यों में ऊर्ध्वमुख एवं अज्ञानी मनुष्यों में अधोमुख वाला कहा गया है। इस प्रकार सर्वत्र समरूप से प्रणव (? कार) ही प्रतिष्ठित है, इसको इस प्रकार से जो जानता है, वही वेदविद् है। ज्ञानी साधकों में यह प्रणव अनाहत रूप से ऊर्ध्वगति वाला होता है।

क्रमशः ...

प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां

अभिनय आकाश

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चार क्रांतिकारियों को 17 दिसंबर (राजेंद्रनाथ लाहिड़ी) और 19 दिसंबर (अशफाकउल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह) को 1927 में फांसी दी गई थी। 19 दिसंबर को देश में शहादत दिवस मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक और देशप्रेम के लिहाज से बहुत महत्व है। देश के इतिहास में काकोरी की घटना की अपनी अलग ही पहचान है। जिसका केवल एक ही उद्देश्य अंग्रेजी शासन के विरूद्ध सरकारी खजाना लूटना और उन पैसों से हथियार खरीदना था।

वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। एक अभियान जिसने

भारतीयों को किसी भी गतिविधि से अपना समर्थन वापस लेने के लिए कहा, जो भारत में ब्रिटिश सरकार और अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है। गांधी ने अंततः स्व-शासन प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह के अपने तरीकों का उपयोग करते हुए, इस आंदोलन को अहिंसक होने की कल्पना की थी। लेकिन असहयोग आंदोलन में शामिल कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जिसने इस आंदोलन से जुड़े बहुत से लोगों को रोष से भर दिया।

गांधी जी का साफ कहना था कि वो एक अहिंसावादी आंदोलन चाहते थे। लेकिन हिंसा की वजह से इसे वापस लेने का फैसला किया गया। लेकिन दूसरे पक्ष यानी युवानों का मानना था कि आंदोलन के लिए उन्होंने अपना करियर, जीवन सब छोड़ा। लेकिन बीच में आंदोलन छोड़ने की सूरत में क्या करेंगें? इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अश्फाक उल्लाह खान भी शामिल थे। जिसके बाद बंगाल और उत्तर के राज्यों में कुछ नए संगठन तैयार हो गए। इनका मकसद भी गोरी हुकूमत से देश की आजादी ही थी। लेकिन ये कांग्रेस और गांधीजी के तौर तरीकों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। इसलिए एक नई पार्टी हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान दोनों ही समूह के संस्थापकों में से थे।

अगस्त 1925 में काकोरी में ट्रेन डकैती एचआरए की पहली बड़ी कार्रवाई थी। 8 नंबर की डाउन ट्रेन शाहजहाँपुर और लखनऊ के बीच चलती थी। उसमें रखा अंग्रेजों का जो खजाना क्रांतिकारियों ने लूटने की योजना बनाई, जिसे वे वैसे भी वैध रूप से भारतीयों का मानते थे। उनका उद्देश्य एचआरए को निधि देना और अपने काम और मिशन के लिए जनता का ध्यान आकर्षित करना दोनों था। ये उस दौर में ये अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। जिस जगह पर इस ट्रेन को रोककर इसका खजाना लूटा गया था। उस जगह का नाम काकोरी है।

लोकसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा

डॉ. आशीष वशिष्ठ

इन दिनों सोशल मीडिया पर नोटों से भरी अलमारियों की कुछ तस्वीरों खूब वायरल हो रही हैं, जिनका संबंध कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू से है। धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की खबरें सुर्खियों में रहीं। ये छापेमारी झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर हुईं। आयकर विभाग की इस छापेमारी में अब तक 351 करोड़ रुपए मिले हैं। साहू के ठिकानों में मिले बेहिसाब धनराशि ने फिर से एक बार देश में भ्रष्टाचार और कालेधन को लेकर बहस छेड़ दी है। इस मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर लगातार तंज कस रही है। राजनीति से इतर ये प्रकरण एक गंभीर मामला है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है। पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर जबरदस्त वार किया गया था। दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ और अधिक सख्ती से पेश आ रही है। इस साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया था, जिनका देश सामना कर रहा है- भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। अब बीती 8 दिसंबर को किया गया एक्स पर उनका पोस्ट देखिए, जनता से जो लूटा है, उसकी पाई-पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान-ए-जंग कर 2024 से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के खिलाफ जबरदस्त प्रहार किया है। इस तरह उन्होंने लोकसभा चुनाव का एजेंडा और टोन को भी सेट कर दिया है।

याद कीजिए पीएम मोदी ने कहा था कि, न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। हालिया पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी तकरीबन हर चुनावी रैली में पीएम भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर-शोर से उठाते थे। कभी महादेव ऐप घोटाला तो कभी खनन घोटाला, कभी लाल डायरी में दर्ज काले कारनामे तो कभी भर्तियों में धांधली और पेपर लीक...।

राजस्थान की ऐसी ही एक रैली में पीएम मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण की बातों को दोहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण देश के 3 बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इन तीनों की ही प्रतीक है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के कांकेर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी कि भ्रष्टाचारियों ने जो कुछ भी लूटा है, उसे लौटाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं से कहता हूं- छत्तीसगढ़ को लूटने वाले चाहे कोई भी हों, चाहे कितने भी ताकतवर हों, उन्हें सब कुछ लौटाना होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जून को पटना में विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक के बाद भी भोपाल में एक सभा में विपक्षी दलों की एकता के प्रयासों पर जमकर चुटकियां ली थीं। पीएम मोदी ने कहा था कि आजकल बार-बार एक शब्द आता है- गारंटी। ये सारे विपक्षी दल भ्रष्टाचार की गारंटी हैं। ये गारंटी हैं लाखों-करोड़ रुपयों के घोटालों की। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इनका एक फोटोशॉप कार्यक्रम हुआ। उस फोटो में जो लोग हैं उन सब का मिल कर टोटल करेंगे तो ये सारे मिल कर कम से कम 20 लाख करोड़ रुपये के घोटाले की गारंटी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर किसी ठोस कार्यक्रम के समाप्त हुई विपक्षी दलों की बैठक पर प्रहार करते हुए कहा कि अकेले कांग्रेस का ही लाखों करोड़ों का घोटाला है। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है और इसीलिए इनकी अगर कोई गारंटी है तो वो है- घोटालों की गारंटी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है, तो मोदी की भी एक गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। आश्चर्य की बात यह है कि केंद्र सरकार के खिलाफ ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों में से किसी ने भी उस समय प्रधानमंत्री के आरोपों का खंडन तक नहीं किया। विपक्षी दल ईडी की कार्रवाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही मात खा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई के मामले में दखल देने से इंकार कर दिया था।

बीती 28 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है और जब अदालत कोई फैसला सुनाती है, तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पूरा देश देख रहा है और समझ भी रहा है। भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है और उसे दीमक की तरह खोखला किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 23 अप्रैल को एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में कहा था कि, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की कार्रवाई से कुछ लोग नाराज हैं। इसके बावजूद वह और उनकी सरकार भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। भले ही उनके विरोधी उनके खिलाफ कितना भी बड़ा गठबंधन बना लें, कार्रवाई नहीं रुकेगी।

भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का प्रहार लगातार जारी है। केंद्र की तरफ़ से संसद में रखी गई जानकारी में भी ये बात सामने आई है। सरकार ने संसद को बताया है कि जुलाई 2014 से दिसम्बर 2020 तक यानी बीते छह साल में 340 बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार, अनियमितता या फ़िर अक्षमता के चलते जबरन रिटायर किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को बल इस बात से मिलता है विपक्ष के कई नेता आज भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं और कई जमानत पर बाहर हैं। विपक्षी नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के ज्यादातर मामलों में अदालत ने कोई राहत नहीं दी है। विपक्ष के लिए बेशक भ्रष्टाचार मिटाने का मुद्दा प्रमुख न हो, पर इस मामले में भारत की स्थिति भयावह है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की 180 देशों की सूची में भारत को 40 अंकों के साथ 85वें पायदान पर रखा गया। निश्चित तौर पर राज्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण ही भारत की यह स्थिति बनी है। विशेषकर विपक्षी दलों की सत्ता वाले राज्यों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह विपक्षी दलों के लिए कभी भी चिंता का विषय नहीं बना।

भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयों को विपक्ष बदले की राजनीति करार देता है। लेकिन हालिया चुनाव नतीजों से उत्साहित केंद्र सरकार इन आरोपों से दबाव में आने वाली नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी को जनता का साथ मिल रहा है। इस तरह उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को बड़ा मुद्दा बनाकर भुनाने के संकेत दे दिए हैं। यह निश्चित है कि जब तक विपक्षी दल भ्रष्टाचार सहित राष्ट्रहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण साफ नहीं करेंगे तब तक एकता होने के बावजूद देश के लोगों का भरोसा जीतना आसान नहीं है। भाजपा विपक्षी दलों को लगातार निशाने पर लेती रहेगी और इस बार लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे की गूंज जोर शोर से सुनाई देगी।

आज का इतिहास

1931 जोसफ ए लियोंस आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने।
1932 बीबीसी ने अपनी विश्व सेवा शुरू की, अब दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर बीबीसी एम्पायर सर्विस है।
1932 बीबीसी ने अपनी अंतरराष्ट्रीय सेवाओं की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से की।
1950 जेन इसेनहोवर उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के कमांडर बने।
1956 आयरिश में जन्मे ब्रिटिश चिकित्सक जॉन बोडकिन एडम्स को उनके 160 से अधिक रोगियों की संदिग्ध मौतों के साथ अनिर्णय के कारण गिरफ्तार किया गया था, हालांकि उन्हें केवल मामूली आरोपों में दोषी ठहराया गया था।
1964 वियतनाम गणराज्य की सेना, गुयेन खान की अगुवाई में दक्षिणपूर्वी के सत्तारूढ़ जंटा ने नागरिक राष्ट्रीय सलाहकार निकाय, हाई नेशनल काउंसिल के एक तख्तापलट को भंग करने और गिरफ्तार करने की पहल की।
1966 एशियाई विकास बैंक की शुरुआत की गयी।
1974 ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोटिंग का जन्म हुआ। इन्होंने अपने करियर में 168 टेस्ट में 13378 और 375 वनडे मैचों में 13704 रन बनाए हैं।
1981 सोलह लोगों की जान चली गई जब एक पेनली लाइफबोट इंग्लैंड के दक्षिण-पश्चिम इलाके से दूर भारी समुद्र में असहाय कोस्टार यूनियन स्टार की सहायता के लिए गई।
1985 याकुतस्क यूनाइटेड एयर ग्रुप फ्लाइट 101/435 को सह-पायलट द्वारा अपहरण कर लिया गया था और चीन में उतारा गया था, जहां उसे पकड़ लिया गया था, जबकि चीनी यात्री उपहार के साथ घर लौट आए थे।
1986 गोर्की में छह साल के आंतरिक निर्वासन के बाद सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने असंतुष्ट आंद्रेईसखारोव को रिहा कर दिया।
1989 कम्युनिस्ट शासन के विरोध में रोमानियाई शहरों में श्रमिको ने हड़ताल किया।
1991 क्रिसमस कैरोल 14 प्रदर्शनों के लिए यूजीन ओ नील थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में खुलता है।
1996 वन्स अपॉन ए मैट्रेस, 187 प्रदर्शन के लिए ब्रॉडहर्स्ट न्यूयॉर्क सिटी में खुलता है।
1997 इंडोनेशिया में मुशी नदी में दुर्घटनाग्रस्त हुई सिल्कएयर फ्लाइट 185 को कप्तान द्वारा हत्या-आत्महत्या के लिए निर्धारित किया गया था।
1998 प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग के दो लेखों को मंजूरी दी, राष्ट्रपति क्लिंटन पर संघीय भव्य जूरी के शपथ के साथ चार्ज करने और न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाया।

राजनीति का नया कुरुक्षेत्र मालवा और भाजपा की दिशा-दशा

अजय बोकिल

हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में से एक और लोकसभा सीटों के लिहाज से भी तीसरे बड़े राज्य मध्यप्रदेश में दोनो प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन की सियासत अब दिलचस्प मोड़ में है। मप्र में विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद सत्तारूढ़ भाजपा अब पूरे घर के बदल डालने की तर्ज पर काम रही है तो इसके जवाब में कांग्रेस ने भी अपने सभी मुख्य सिपहसालार ताबड़तोड़ बदल दिए हैं। मोटे तौर पर बदलाव का यह फार्मूला फ्रेश चेहरों को आगे लाने, जातीय व क्षेत्रीय समीकरण साधने और आने वाले कम से कम एक दशक राजनीति कर सकने वालों को कमान सौंपने की नीयत से लागू किया गया है। खास बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने इस बार राज्य के अपेक्षाकृत समृद्ध और प्रगत क्षेत्र मालवा अंचल को केन्द्र में रखा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता इसी अंचल से गुजरता है।

मप्र की राजनीति में यह अभूतपूर्व संयोग है कि अब राज्य का मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी मालवा अंचल से ही है। यानी मालवा अब प्रदेश की राजनीतिक महाभारत का नया कुरुक्षेत्र है। जो मालवा पर काबिज होगा, वह भोपाल में सत्तासीन होगा। मध्यप्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इनमें से 8 अकेले मालवा से हैं और इसी क्षेत्र में विधानसभा की 50 सीटें हैं। इनमें अगर निमाड़ को भी जोड़ लिया जाए तो ये संख्या लोकसभा की 10 और विधानसभा की 66 सीटें होती हैं। इस बार बीजेपी ने 66 में से 48 सीटों पर जीत हासिल कर कांग्रेस को बहुत पीछे ठेल दिया है। भाजपा ने अपना नया मुख्यमंत्री जिन डॉ. मोहन यादव को बनाया है, वो मालवा के उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं और ओबीसी चेहरा हैं। जबकि उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मालवा के ही मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ सीट से विधायक हैं। इसके पीछे संदेश राज्य और राज्य से बाहर भी ओबीसी और आदिवासी समीकरण को साधना है। यही कारण है कि कांग्रेस में नेतृत्व का जो पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, वह मालवा को ध्यान में रखकर ही हुआ है। इसमें जातिगत समीकरण भी साधा गया है।

नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ओबीसी से हैं तो उमंग सिंघार आदिवासी हैं। इस बदलाव के साथ ही कांग्रेस आला कमान ने राज्य में कांग्रेस के दो पुराने दिग्गज चेहरों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को रिटायरमेंट का

साफ संदेश दे दिया है, जबकि भाजपा में यह संदेश थोड़ा अलग ढंग से दिया गया है।

अलबत्ता राज्य में भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे सीएम पद के प्रबल दावेदार नेताओं को संदेश दिया गया है कि उन्हें मुख्यधारा से अभी बाहर नहीं किया गया है, यही काफी है। दोनों पार्टियों में इस पीढ़ीगत बदलाव का युवाओं ने आम तौर पर स्वागत किया है। लेकिन इसी के साथ कुछ गंभीर सवाल भी फिजा में तैर रहे हैं। वो कांग्रेस में इस जवाबी सोशल इंजीनियरिंग और नई पीढ़ी पर दांव लगाने को लेकर हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है तो वह पहले भी दूसरे राज्यों में ऐसा करती रही है और अपने मजबूत संगठनात्मक ढांचे के दम पर इस प्रयोग को (कुछ अपवादों को छोड़ दें तो) सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाती रही है। वहां बगावत की गुंजाइश ज्यादा नहीं होती। कार्यकर्ता आलाकमान के फैसले को सिर आंखों पर रखकर चलता है। इसलिए ऐसे जोखिम ज्यादातर सफल दांव में बदल जाते हैं।

मप्र में नए सीएम डॉ. मोहन यादव आला कमान की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेंगे, यह अभी देखने की बात है। पर उन्होंने पद संभालते ही टी 20 की तर्ज पर बैटिंग करने का संकेत दे दिया है। जानकारों का मानना है कि भाजपा ने मोहन यादव पर दांव मप्र की ओबीसी राजनीति कम आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार में यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के उद्देश्य से किया है। मोहन यादव यह काम कितना कर पाएंगे, इसी से उनका राजनीतिक भविष्य तय होने की संभावना ज्यादा है। अगर वो नाकाम रहे तो भाजपा के पास रिजर्व में दूसरे अनुभवी खिलाड़ी हैं ही। वैसे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पद संभालते ही दो अहम संदेश देने की कोशिश की है, एक तो वो कट्टर हिंदुत्व की राह चलेंगे, दूसरा विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते वो अंधविश्वासी नहीं हैं।

उम्मीद की जा सकती है कि मोहन राज में अंध श्रद्धा की बजाए तार्किक और प्रगतिशील हिंदुत्व को ज्यादा महत्व मिलेगा। जहां तक मप्र में जातीय समीकरण साधने की बात है तो मोहन यादव का चेहरा इसलिए भी चौंकाने वाला था, क्योंकि राज्य में यादवों की संख्या अन्य दूसरी ओबीसी जातियां जैसे कि लोधी, कुर्मी, गूजर आदि की तुलना में कम है और यादव किसी एक पॉकेट में केन्द्रित होने के बजाए पूरे राज्य में फैले हैं। कुल मिलाकर भाजपा ने मोहन यादव के बहाने पड़ोसी राज्यों का जातीय समीकरण साधने का राजनीतिक योगासन किया है। जहां तक पीढ़ी परिवर्तन की बात है तो मप्र कांग्रेस में भी वह आलाकमान के निर्देश पर ही हुआ है। माना जा रहा है कि अब पार्टी की कमान परोक्ष रूप से राहुल गांधी पूरी तरह अपने हाथ में ले रहे हैं और राज्य में नए चेहरे उन्हीं की पसंद हैं।

इसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी के पुराने दिग्गजों को अब रिटायरमेंट का सिग्नल दे दिया गया है और संगठन में टीम राहुल अब अपने ढंग से आकार लेने लगी है। लेकिन कांग्रेस में अहम सवाल यह है कि अगर इन नए चेहरों को पुराने दिग्गजों का साथ न मिला या भीतरघात की सियासत जारी रही तो ये टीम कैसे परफॉर्म कर पाएगी?

पहले से ही गुटबाजी और अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस में मनभेदों के खाने ज्यादा कुलबुलाने नहीं लगेंगे? वैसे भी कांग्रेस में इस बदलाव का खास असर लोकसभा चुनाव में दिखने की संभावना बहुत कम है। अलबत्ता इसका प्रभाव अगले विधानसभा चुनाव में जरूर दिख सकता है क्योंकि तब तक कांग्रेस में युवा चेहरों की नई टीम तैयार हो सकने की उम्मीद है।

बहरहाल अब मालवांचल मप्र की राजनीति का नया कुरुक्षेत्र है, जहां से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनो की रणनीतियों का संचालन होना है। यहां हो रहे राजनीतिक प्रयोगों की गूंज राष्ट्रीय स्तर भी सुनाई देने की संभावना है। मालवा को ये महत्व अर्से बाद मिला है। फर्क यह है कि कभी कांग्रेस का गढ़ रहा मालवा बीते पांच दशकों से भगवा किले में तब्दील हो चुका है।

अखिलेश-तेजस्वी के खिलाफ भाजपा का प्लान

अंकित सिंह

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जबरदस्त जीत के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री के रूप में चौंकाने वाला फैसला लिया। इन तीनों ही राज्यों में नए चेहरों पर दांव लगाया। राजस्थान में जहां भजन लाल शर्मा के रूप में भाजपा ने एक ब्राह्मण चेहरे को आगे किया जो पहली बार ही विधायक बने थे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय पर बड़ा दांव लगाया है जो आदिवासी समाज से आते हैं। हालांकि, भाजपा ने जातीय राजनीति को संतुलित करने के लिए सबसे बड़ा खेल मध्य प्रदेश में खेला है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। इसके जरिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ-साथ हरियाणा को भी बड़ा संदेश दे दिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वापसी तो मुश्किल मानी जा रही थी। लेकिन दावा किया जा रहा था कि उनकी जगह भाजपा किसी ओबीसी चेहरे पर ही दांव लगाएगी। जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में थी वह था प्रहलाद सिंह पटेल का था। वह भी एक एक बड़े ओबीसी नेता हैं। हालांकि, भाजपा ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को आगे किया जो की यादव समाज से आते हैं। ओबीसी में यादवों का बहुत ही दबदबा है। मध्य प्रदेश में यादवों की आबादी की बात करें तो 14 फ़ीसदी है। हालांकि, इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि शिवराज सिंह की जगह बीजेपी ने एक अन्य ओबीसी चेहरा पर दांव लगाया लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल, भाजपा मोहन यादव के जरिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगी जहां यादव एक प्रभावशाली समूह है। बिहार और यूपी के यादव का कितना प्रभाव है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का राजनीति इन्हीं से जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह भी है कि मोहन यादव की पत्नी सीमा उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की रहने वाली है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। माना जाता है कि लालू यादव की यादव वोट बैंक पर पकड़ मजबूत है। वहीं दिलचस्प बात यह भी है कि बिहार एकमात्र ऐसा हिंदी भाषा राज्य है जहां बीजेपी कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बन पाई और इसका बड़ा कारण यादव का वोट है जो भाजपा के पाले में अब तक आ नहीं पाया है। इसके साथ ही भाजपा ने राहुल गांधी को भी जवाब दे दिया राहुल गांधी लगातार ओबीसी पर जोर दे रहे थे। मोहन यादव के नाम में यादव सरनेम है। इससे भी भाजपा को फायदा हो सकता है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को प्रमुख यादव नेता माना जाता है। तो वहीं यूपी में मुलायम सिंह यादव के बाद अब अखिलेश यादव प्रमुख यादव नेता हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने यादवों को बड़ा संदेश दे दिया है। भाजपा ने यह भी बता दिया है कि हमारे लिए परिवारवाद मायने नहीं रखता है। हम एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में एक एजेंडा भी सेट कर दिया है। इन दोनों ही राज्यों में जातीय जनगणना को लेकर विपक्षी दल आक्रामक है। यही कारण है कि यादव वोट बैंक में सेंध लगाने में मोहन यादव का चेहरा भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बिहार में यादवों की संख्या 14 फीसदी से ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यादव का जबरदस्त दबदबा है। वही हरियाणा और राजस्थान में भी उनके वोट मायने रखते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने स्वर्ण और दलितों को भी खुश कर दिया। मध्य प्रदेश में भाजपा ने दो उपमुख्यमंत्री बनाए हैं। पहले हैं जगदीश देवड़ा जो की एक दलित चेहरा है जबकि दूसरे हैं राजेंद्र शुक्ला जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इसे भी भाजपा का एक बड़ा प्रयोग माना जा रहा है। भाजपा ने इन दोनों के जरिए जातीय संतुलन पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश में दलितों की आबादी भी अच्छी खासी है। वहीं, ब्राह्मणों के जरिए सवर्णों को भी साथ जा सकता है जो लगातार भाजपा के कोर वोटर माने जाते रहे हैं।

नेतृत्व में सर्जनात्मक दृष्टि होने के फायदे

गिरीश्वर मिश्र

राजनीति की यात्रा में गतिशीलता और दूरदृष्टि की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक इसके विपरीत भारत के राजनैतिक माहौल में आ रही थकान और उम्रदराज नेताओं की सत्ताप्रियता तथा बड़े कद के नेताओं द्वारा अतिरिक्त मोहवश अपने परिवार या वंश में ही सत्ता को सीमित और संकुचित रूप से बांध कर सुरक्षित रखने की परंपरा के चलते अजीबोगरीब शिथिलता आने लगी है जो देशहित के विरुद्ध तो है ही, स्वयं राजनैतिक दलों के ही पक्ष में नहीं जाती। ऐसी परिस्थिति से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों तरह के दल जूझ रहे हैं। नई पीढ़ी को इंतजार करना पड़ता है या फिर कुछ शॉर्ट कट के उपाय करने होते हैं। इस तरह से पनप रही जड़ता के बीच राजनीति भ्रष्टाचार का विग्रह होती जा रही है। जातीय अस्मिता की बैसाखी पार्टियों के संस्कार को जाति, धन और बाहुबल के अधीन करती जा रही है। भारतीय समाज की नब्ज पकड़ने के लिए उद्यत होने पर छोटी-छोटी अस्मिताओं को उभारा जाता है और कभी-कभी उसका फायदा भी मिल जाता है। पांच राज्यों के हुए ताजे चुनाव के नतीजे कई मिथकों और पूर्वानुमानों को ध्वस्त करने वाले सिद्ध हुए हैं। उनसे भी ज्यादा चौंकाने वाले तौर-तरीके राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन में उभरे। भाजपा ने चुनाव पूर्व इनका ऐलान नहीं किया था और पार्टी के नाम पर कमल और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का जोखिम उठाया। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के नामों और उनके अच्छे-बुरे कार्यों से सभी परिचित थे। दूसरी ओर भाजपा ने लोकतंत्रीयता का बाना अपनाते हुए निर्णय खुला रखा था। चुनाव परिणाम के बाद भाजपा ने नए और कम परिचित चेहरों को मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर कर्मठता और जनरुचि का आदर करते हुए साहसिक कदम उठाया। राजनीति को नया अर्थ देते हुए विरोधियों को अस्त-व्यस्त किया है और अपनी छवि को एक नए आयाम के साथ प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। स्पष्ट ही 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव दृष्टि में हैं पर राजनीति की यह शैली एक पैराडाइम शिफ्ट या सोच में बड़े बदलाव का बड़ा संकेत दे रही है। विचारधारा की और आचार में गंभीरता की ओर ये बढ़ते कदम आशा बंधाने वाले हैं। यह ऐसे मौके पर हो रहा है जब मोदी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आशा है इस तरह के परिवर्तन के जनहितकारी परिणाम होंगे।

अटल-आडवाणी युग के नेताओं को दरकिनार

अजय सेतिया

भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी देर जरुर लगाई, लेकिन अब तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री तय हो चुके हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में मुख्यमंत्री तय करते समय देर नहीं लगाई। लेकिन इसमें से ही कुछ समझने की जरूरत है। कांग्रेस ने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद यह स्वीकार कर लिया कि तेलंगाना में उसकी जीत का कारण राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी हैं। जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पार्टी को के. चन्द्रशेखर राव के विकल्प के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पृष्ठभूमि के नहीं हैं, वह इस से पहले तेलुगु देशम पार्टी में थे और छात्र जीवन में संघ के छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। दूसरी तरफ तीनों राज्यों में भाजपा को जिताने का श्रेय सीधे नरेंद्र मोदी को दिया गया है। भाजपा ने इन तीनों राज्यों में पनपी गुटबाजी से निजात पाने के लिए किसी भी चेहरे को सामने रख कर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्यों में पार्टी लंबे समय से गुटबाजी का शिकार थी। गहन विचार विमर्श के बाद फैसला हुआ था कि गुटबाजी को खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बजाए पार्टी अपनी जड़ों में लौटे और सिर्फ चुनाव निशान को आगे किया जाए।

जब कमल के निशान पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ था, तभी यह तय हो गया था कि इन तीनों राज्यों में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। चुनावों से पहले जब मध्यप्रदेश में दो केन्द्रीय मंत्रियों सहित छह सांसदों को टिकट दिया गया, तो मीडिया में इसका मतलब यह निकाला गया कि इनमें से कोई शिवराज सिंह चौहान का विकल्प बनेगा। राजस्थान में भी जब छह सांसदों को टिकट दिया गया तो वहां भी यही अटकल लगाई गई कि इनमें से कोई वसुंधरा राजे का विकल्प बनेगा। छत्तीसगढ़ में भी एक

केन्द्रीय मंत्री सहित चार सांसद भेजे गए थे। लेकिन इनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। भाजपा को तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री तय करने में आठ दिन लग गए। इससे यह भी साबित हुआ कि भाजपा ने पहले यह तो तय किया था कि आमूलचूल परिवर्तन करना है, लेकिन यह तय नहीं किया था कि स्थापित चेहरों का विकल्प कौन होगा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आदिवासी, मध्यप्रदेश में ओबीसी मोहन यादव और राजस्थान में ब्राह्मण भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो चुका है।

इनमें से किसी के भी मुख्यमंत्री बनने का किसी को कोई अंदाज तक नहीं था। ये तीनों को भी अनुमान नहीं था कि वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भजन लाल शर्मा तो पहली बार ही विधायक बने हैं। भाजपा के तीनों मुख्यमंत्रियों की विशेषता यह है कि वे संघ पृष्भूमि के हैं, और तीनों ही विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। विद्यार्थी परिषद इस बात पर गर्व कर सकती है कि पांच राज्यों में चुनाव हुए और चार राज्यों में उसके कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे। भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाते समय जातियों को साधने की रणनीति के तहत प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन चुनावों से पहले महिला सशक्तिकरण का जो संदेश मोदी दे रहे थे, वह थोड़ा धुंधला जरूर पड़ा है, क्योंकि कोई महिला मुख्यमंत्री भी नहीं बनाई गई। महिला उप मुख्यमंत्री भी सिर्फ राजस्थान में दीया कुमारी बनाई गई हैं। छतीसगढ़ और मध्यप्रदेश में महिला उपमुख्यमंत्री नहीं बनाई गई। नए मुख्यमंत्रियों का नाम सामने आने के बाद यह भी साफ़ हो गया कि भाजपा ने अपने 21 सांसदों को राज्यों में मौजूदा नेतृत्व के विकल्प के तौर पर नहीं भेजा था। भाजपा ने विधानसभा चुनावों के बहाने लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों की भी छंटाई कर ली। भाजपा ने तीनों ही राज्यों में नया नेतृत्व उभारने का फैसला कर लिया था।

बड़े पैमाने पर सांसद और नए चेहरे उतार कर भाजपा यह संदेश देने में कामयाब हो गई थी कि भाजपा पुराने चेहरों को मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपेगी। उसका असर चुनाव नतीजों में देखने को मिला, भले ही वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह तीनों ही विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इन तीनों को हटाए जाने के बाद 2014 से पहले का यानी अटल-आडवानी के जमाने के छत्रपों को हटाने का काम लगभग पूरा हो गया है। भाजपा अब नए नेतृत्व के साथ 2024 के लोकसभा चुनावों में उतरेगी। भाजपा विरोधी इस बात को कभी समझ ही नहीं सकेंगें कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की थी, तभी उसने लोकसभा चुनाव की तैयारी भी साथ ही शुरू कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री तय कर के यह संदेश भी दिया है कि वह किसी एक चुनाव को हार-जीत की दृष्टि से ही नहीं देखती, हार हो या जीत, उसी में से भविष्य की रणनीति भी निकालती है। देश का शायद ही कोई पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक होगा, जिसने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने को उतरप्रदेश बिहार में चुनाव जीतने की रणनीति के तौर पर नहीं समझा होगा। लेकिन जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, क्या तब किसी ने सोचा था कि भाजपा मध्यप्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति का रास्ता निकाल लेगी।

वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म या मिलेगी कोई नयी जिम्मेदारी ?

निरंजन परिहार

राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की सारी कोशिशें करने के बावजूद असफल रहीं वसुंधरा राजे के स्थान पर मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली है और अब राजे की राजनीतिक संभावनाओं पर चर्चा होने लगी है। भाजपा ने जब मुख्यमंत्री पद के लिए शर्मा के रूप में नए चेहरे को चुना तो तारीफ तो बहुत हुई और यह भी कहा गया कि इस चयन से आम कार्यकर्ता में यह विश्वास बढ़ा है कि हर समर्पित कार्यकर्ता कल किसी भी पद पर पहुंच सकता है। लेकिन यह भी सवाल उठा कि राजस्थान की सबसे मजबूत नेता वसुंधरा राजे अब क्या करेंगी? या पार्टी अब उनके लिए क्या सोच रही है?

सवाल इसलिए है कि वसुंधरा राजे प्रदेश की सबसे लोकप्रिय नेता हैं और फिर भी उनकी बजाय भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना गया। 70 साल की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में अब भी लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके लिए पार्टी का क्या प्लान हैं, इस बारे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने फ़िलहाल पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद मुख्यमंत्री पद न दिए जाने के बाद उनके भविष्य पर बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व राजे को पार्टी के भीतर या केंद्र सरकार में मौक़ा दे सकता है।

राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रहने से पहले वसुंधरा राजे केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री रही हैं। वसुंधरा राजे दो बार दमदार मुख्यमंत्री रही हैं और फिलहाल बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 2014 में बीजेपी जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सत्ता में आई तो वसुंधरा को केंद्र की राजनीति में आने के लिए कहा गया था, यह तब की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सबसे करीबी साथी अमित शाह देश भर में पार्टी का विस्तार कर रहे थे और साथ ही उस पर अपनी पकड़ भी मज़बूत कर रहे थे।

मगर तब वसुंधरा ने इससे इनकार कर दिया था। फिर वह राजस्थान में पार्टी के नेताओं और विधायकों के बीच अपने वफ़ादारों की फौज का विस्तार करती हुई राज्य में बीजेपी को मजबूत करने के साथ ही खुद की जड़ें भी गहरी करती जा रही थीं। इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले जब उनको केंद्र में ले जाने की बात चली, तो उन्होंने खुद ही यह ऐलान तक कर दिया कि %मैं राजस्थान से बाहर कहीं नहीं जाने वाली, मेरी डोली राजस्थान आई थी और अब मेरी अर्थी ही राजस्थान से जाएगी।%

राजस्थान में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे के भविष्य का प्लान तैयार कर लिया था। राजस्थान की राजनीतिक समझ रखनेवाले कहते हैं सन 2018 में जब राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई, तभी वसुंधरा राजे के बजाय बीजेपी नेतृत्व ने उनकी जगह राजस्थान में नए नेतृत्व को आगे लाने का निर्णय कर लिया था। इसी कारण उनको दरकिनार करते हुए छोटे छोटे प्रतिद्वंदियों को ताकतवर बनाया जाता रहा।

जानकार कहते हैं कि इसके बावजूद राजनीतिक रूप से बेहद जिद्दी स्वभाव की वसुंधरा राजे अपने स्वभाव के मुताबिक राजस्थान में अपनी ताकत दिखाने के नुस्खे तलाशती रही और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की राह अपने स्तर पर मजबूत करती रही। हालांकि बीजेपी नेतृत्व भी किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के अपने लक्ष्य पर अटल रहते हुए हर तरह से वसुंधरा को मुख्यधारा से दूर ही रखे रहा। फिर भी, बीजेपी के नेताओं द्वारा बीच बीच में जब तब उनको राजस्थान से बाहर भेजे जाने की चर्चा चली, तो वह दृढ़ता से डोली और अर्थी वाला अपना लोकप्रिय जुमला उछालकर जिद पर अड़े रहने के संदेश देती रही और विधायकों व नेताओं का साथ व समर्थन भी जुटाती रही।

इस बार के विधानसभा चुनाव में भी वसुंधरा ने पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की, और हालांकि बीजेपी आलाकमान ने उनके समर्थकों और विश्वासपात्रों को बड़ी संख्या में टिकट भी दिए, लेकिन उनके चेहरे पर वोट मांगने के बजाय कमल के निशान को पार्टी का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करते ही उन्हें दरकिनार करके भजनलाल शर्मा जैसे वसुंधरा राजे से बेहद अल्प राजनीतिक कद के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया।

अब जब बीजेपी ने राजस्थान में नेतृत्व का स्वरूप ही बदलकर वसुंधरा से फोकस शिफ्ट कर दिया है, तो सवाल किया जा रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? राजनीति से जुड़े लोगों और राजनीतिक विश्लेषकों की इस मामले में अलग अलग राय है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि बीजेपी टेलेंट को जाया नहीं करती, किसी न किसी रूप में उनका उपयोग करती ही है।

इसी तथ्य के अनुरूप वसुंधरा राजे को केंद्र सरकार में या संगठन में कोई सक्रिय जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि, वसुंधरा राजे पार्टी से मिले किसी प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी या नहीं, इस पर अलग अलग मत हैं। वसुंधरा राजे के एक करीबी का कहना है कि यह पूरी तरह से राजे के निर्णय पर ही निर्भर रहेगा कि वे दिल्ली से मिलने वाले किसी भी तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं या नहीं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बहुत संभावना इस बात की भी है कि केंद्र अपनी ओर से वसुंधरा राजे को कोई प्रस्ताव दे ही नहीं।

हालांकि, यह भी तय है कि %डोली और अर्थी% वाला उनका दांव भजनलाल शर्मा को नेतृत्व मिलने के बाद अब ठंडा पड़ गया है और संभव है कि वे देश या दिल्ली में कोई सम्मानजनक पद लेकर तत्काल राष्ट्रसेवा में लग जाए, या फिर लोकसभा चुनाव की प्रतीक्षा करे, ताकि चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री पद की संभावना जग सके। वसुंधरा राजे की राजनीति जानने वाले कहते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के, %मैं अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, ये मेरा काम नहीं है% बयान के बाद वसुंधरा राजे पर भी ये दबाव बना है कि वे भी केंद्र से कुछ ना मांगें।

हालांकि, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वसुंधरा राजे के रिश्ते रहे हैं, तथा तीनों ही अपने अपने स्तर पर राजनीतिक रूप से बेहद सख्त और लगभग अटल - अविचल रहने वाले हैं, उससे तो यह संभावना कतई नहीं है कि तीनों में से कोई एक भी झुकेगा। फिर, वसुंधरा राजे भी शिवराज सिंह की तरह ही मांगना तो पसंद नहीं करेंगी, यह सब जानते हैं।

ऐसे में, सियासी शतरंज पर भले ही यह कहा जाता रहा हो कि राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है लेकिन जब संभावनाएं खुद ही भावनाओं का खेल बन जाए, तो राजनीति खेल से ज्यादा और कुछ भी नहीं होती। फिर भी कहना मुश्किल है कि वसुंधरा राजे के साथ खेल हो गया और उनका खेल खत्म हो गया है। लेकिन खेल की गेंद किसके पाले में है, यह भी साफ है।

बचपन

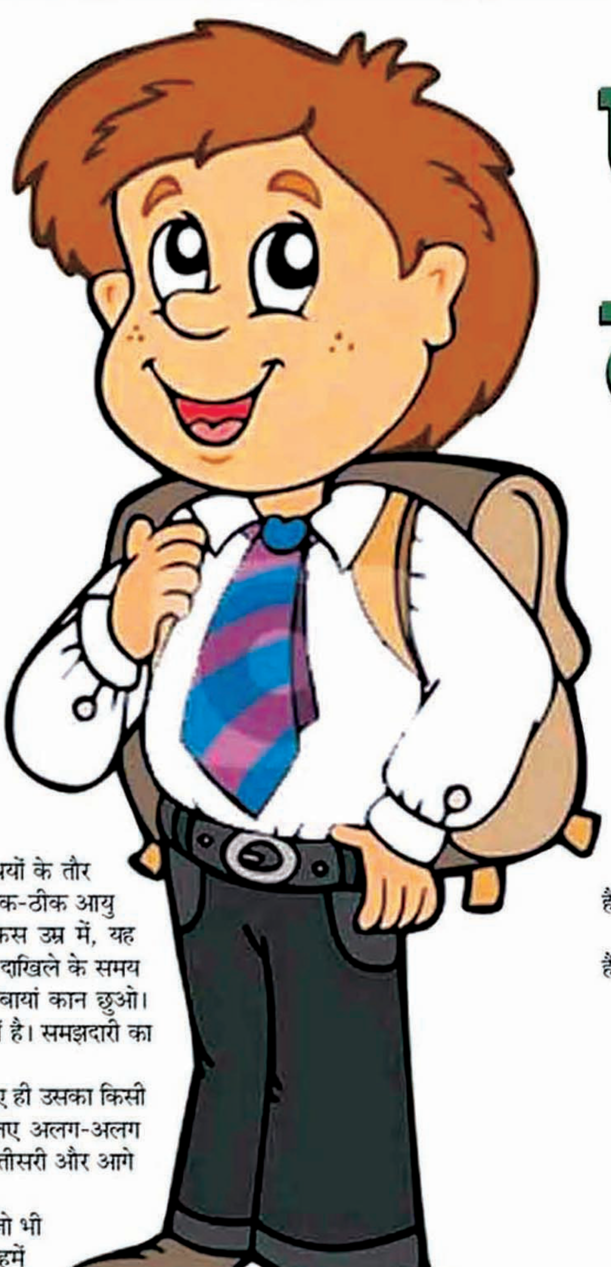

बायां कान छू लिया तो हो गया एडमिशन

बहुत साल पहले की बात है। उस समय में जन्मदिन तिथियों के तौर पर याद रखे जाते थे। तिथियां बदलती थीं तो बच्चे की ठीक-ठीक आयु बता पाना मुश्किल होता था। अब स्कूल कब भेजें, किस उम्र में, यह सवाल उठा, तो हमारे ज्ञानी गुरुजनों ने इसका एक तरीका निकाला। स्कूल में दाखिले के समय बच्चे से कहा जाता कि अपने दाएं हाथ को सिर के ऊपर से ले जाते हुए बायां कान छुओ। अगर बच्चा ऐसा कर पाता तो उसे दाखिला मिल जाता। यह मामूली टेस्ट नहीं है। समझदारी का बिलकुल सरल परीक्षण है।

बच्चे की समझ और उसके शरीर व मस्तिष्क की परिपक्वता को देखते हुए ही उसका किसी स्कूल में दाखिला कराया जाता था। समझ को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग क्लासेस होती हैं। केजी 1, केजी 2, फिर पहली कक्षा और इसी तरह दूसरी, तीसरी और आगे की तमाम कक्षाएं।

दरअसल, कक्षाओं पर आधारित शिक्षा का मकसद होता है कि विद्यार्थी जो भी सीखें उसे एक सिलसिलेवार तरीके से सीखें। अलग-अलग कक्षा के होने से हमें उसी के अनुरूप या फिर यूं कहें कि समकक्ष संगी-साथी मिलते हैं। सोचो, अगर आपको पहली कक्षा में न बैठाकर सीधे आठवीं या दसवीं कक्षा के विद्यार्थी के साथ बैठा दिया जाए तो कैसा लगेगा? विभिन्न कक्षाओं के होने से कोई भी बच्चा क्रमश धीरे-धीरे चीजों को सीखता है। कक्षाएं होने से विद्यार्थी की समझने की क्षमता के अनुरूप ही विषय सामग्री बनाई जाती है, ताकि उस विषय सामग्री यानी किताबें, कोर्स आदि उस दरे के बच्चे को समझने में दिक्कत न करें। कक्षाओं के होने से आपको एक फायदा भी है। आपके पड़ोस में रह रहे राहुल को भी वहीं चीजो पढ़नी होती हैं। भले ही वो आपसे पढ़ने में कितना ही तेजी से क्यों न हो। इस तरह आप अपनी ही आयु के अन्य बच्चों से काफी कुछ सीख भी सकते हैं। अपनी ही आयु के बच्चों के साथ एक क्लास में बैठने से खुद को सहज भी महसूस करते हैं। यानि क्लास रूप वो स्थान है जहां सभी एक आयु के, एक-सा कोर्स पढ़ने वाले और एक सी ही परीक्षा देने वाले, कोई बड़ा-छोटा नहीं, कोई भेदभाव नहीं।

पेड़ पौधे भी देते हैं सीख

प्रकृति में पेड़-पौधे, सूरज, हवा, हिमकण और सितारें सब शामिल हैं। ये सभी हमें जीवन देते हैं। इनका वजूद हम सबके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बिना कुछ कहे ही ये हमें सब कुछ बताते हैं बस जरूरत है तो उन्हें समझने की।

धरती को हरी-भरी बनाने के साथ हमें ऑक्सीजन की सौगात देते हैं, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं।

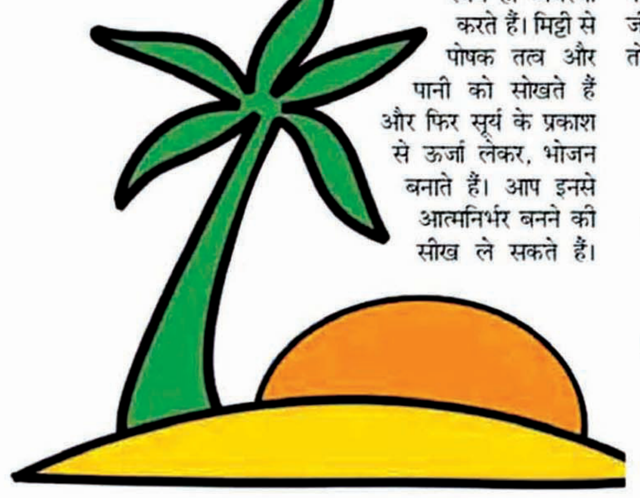

पेड़-पौधे अपने भोजन की स्वयं ही व्यवस्था करते हैं। मिट्टी से पोषक तत्व और पानी को सोखते हैं और फिर सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर, भोजन बनाते हैं। आप इनसे आत्मनिर्भर बनने की सीख ले सकते हैं।

पेड़ की छांव तेज धूप में आपको शीतलता प्रदान करती है। वहीं इसके फल बहुत मीठे और रसीले होते हैं। पेड़ के फल तो आपके और हमारे लिए ही होते हैं। इस तरह से ये हमें सुरक्षा और परोपकार की सीख देते हैं।

इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये चाहें कैसे भी टेढ़े-मेढ़े हों, दूसरे पेड़ ही तरह नहीं बनने की कोशिश करते। यानी इन्हें खुद पर और अपनी काबलियत पर नाज होता है। यानि आप जो भी हो जैसे भी हो, वही रहना चाहिए। आत्मविश्वास से भरपूर बने रहना चाहिए। ये कुछ भी बर्बाद नहीं करते, अपने पोषक तत्वों को धरती से सोख लेते हैं। समय को बिना गंवाए अपने विकास के लिए लगातार लगे रहते हैं। पेड़ो से आप ये चार चीजें और भी सीख सकते हैं। ऑक्सीजन आपको जीवन देती हैं परन्तु यदि आपमें आत्मनिर्भता, सुरक्षा जैसे गुण आ जाएं तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।

पहेलियां

1. मूझमें भार सदा ही रहता
जगह घेरना मुझको आता
हर वस्तु से गहरा रिश्ता
हर जगह मैं पाया जाता।
2. ऊपर से नीचे बहता हूं
हर बर्तन को अपनाता हूं
देखो मुझको गिरा न देना
वरना कठिन हो जाएगा
भरना।
3. लोहा खींचू ऐसी ताकत है
पर रबड़ मुझे हराता है
खोई सूई में पा लेता हूं
मेरा खेल निराला है।

उत्तर

1. गैस, 2. द्रव्य, 3. कांच

जैरी भाग, टॉम आया, टॉम बच, जैरी आया

टॉम हो या जैरी, दोनों एक-दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। दोनों किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते, बस, छीनना चाहते हैं, तो एक-दूजे का सुकून। यानि बस तंग करना ही मकसद है। इनके खेल बड़े मज़ेदार होते हैं।

आपको भी पंसद हैं न। तो चलिए, कुछ जानते हैं इनके बारे में -

गर्मी के दिन थे। जैरी अपने घर में चादर ओढ़े आराम से सो रहा था। तभी उसके नाक में पनीर की खुशबू ने प्रवेश किया। पनीर उसे बहुत पसंद था, वह पलंग से उछल पड़ा और उस दिशा में चल पड़ा, जहां से खुशबू आ रही थी। अपने घर के छोटे-से दरवाजे से निकलते ही उसे सामने पनीर का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई दिया। वह खुशी से उछल पड़ा, हुर्रर्र..। उसके मुंह से लार टपकने लगी। जैसे ही उसने टुकड़े की ओर हाथ बढ़ाया, वैसे ही पीछे से टॉम ने उसे पकड़ लिया। जैरी समझ गया था कि टॉम ने ही उसे पनीर का लालच देकर फंसाया है। टॉम ने जैसे ही जैरी को खाने के लिए अपना मुंह खोला, जैरी ने उसके मूंछों के बालों को ज़ोर से खींच दिया। दर्द के कारण जैरी के हाथों से टॉम छूट गया। जैरी भागा और टॉम भी उसके पीछे-पीछे भागा। इस तरह फिर से शुरू हो गया चूहे-बिल्ली का वह खेल, जिसके करोड़ो बच्चे दीवाने हैं।

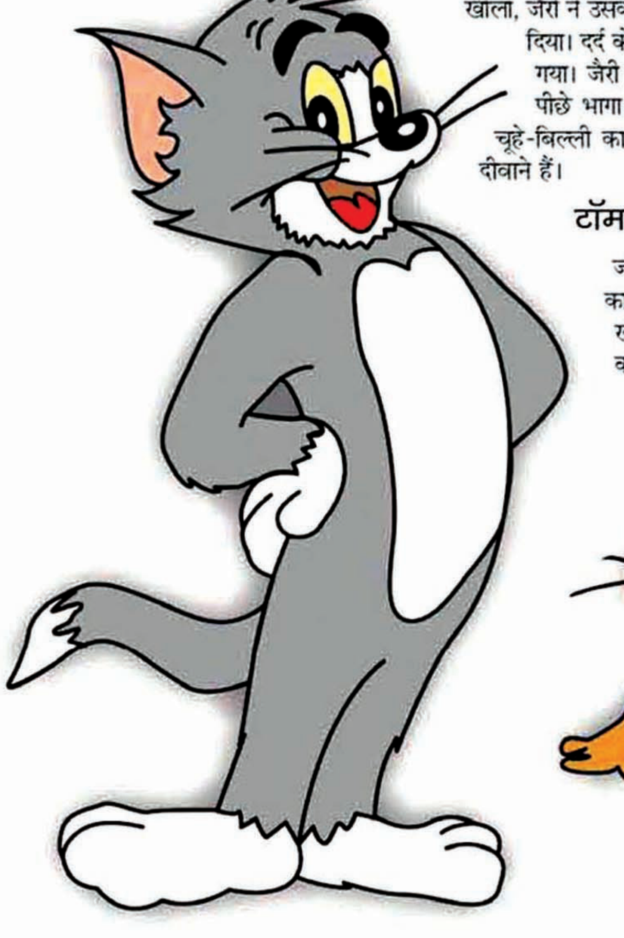

टॉम एंड जैरी का जन्म

जोसफ बारबेरा बैंकिंग हमेशा कागज़ों पर आड़ी-तिरछी लकीरें खींचकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किया करते थे। हालांकि, उनका मकसद बैंकिंग के क्षेत्र में काम करने का था लेकिन उनको काटरून बनाने का भी काफी शौक था। उनके काटरून जल्द ही पत्र-पत्रिकाओं में छपने भी लगे। 1930 के दशक के आखिरी में मैट्रो गोल्डवेन मेयर फिल्म स्टूडियो में उनकी मुलाकात हाना से हुई। इसी मुलाकात में दोनों ने एक ऐसा कार्टून सीरियल बनाने का सोचा, जो एक घरेलू बिल्ली और एक चूहे के बीच लगातार चलने वाली दुश्मनी पर केन्द्रित हो। इसी सोच के साथ उन्होंने टॉम एंड जैरी काटरून पात्रों को छोटे पर्दे पर साकार किया।

जोसेफ-हाना की जोड़ी ने 17 साल के सफर में टॉम एंड जैरी सीरीज़ के लिए सात ऑस्कर पुरस्कार हासिल किए और कुल 14 बार इन्हें पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।

मज़ेदार है चूहे-बिल्ली की यह खेल

एक शरारती चूहा और एक खुराफाती बिल्ली, अगर एक ही घर में हों, तो दिलचस्प घटनाओं की भरमार हो जाती है। टॉम एंड जैरी के द्वारा एक दूसरे का पीछा करने और आपसी लड़ाई में हास्यास्पद भिड़ंत शामिल है। इसी कारण 70 सालों से लेकर आज तक यह दुनियाभर में न केवल बच्चों द्वारा बल्कि उनके अभिभावकों द्वारा भी पसंद किया जाता है। भारत में इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि टॉम एंड जैरी के कार्यम हिंदी के साथ ही अंग्रेजी, तमिल और तेलुगू भाषाओं में भी प्रसारित किए जाते हैं।

आखिर यह भाग-दौड़ क्यों?

प्रत्येक कार्टून फिल्म की कहानी आमतौर पर जैरी को पकड़ने के लिए टॉम के अनगिनत प्रयासों और उसके कारण हुई हाथापाई और दौड़ा-भागी पर आधारित होती है। इनको देखकर यह समझना मुश्किल है कि आखिर ?यों टॉम, जैरी का इतना अधिक पीछा करता है। काटरून को देखकर जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसके हिसाब से कुछ कारणों में एक बिल्ली का एक चूहे के साथ बैर, अपने मालिक के आदेश का पालन, टॉम को सौंपे गए कार्यो को जैरी द्वारा बिगाड़ने की कोशिश, जैरी द्वारा टॉम के मालिक का भोजन खा जाना, जिसकी निगरानी का जिम्मा टॉम को सौंपा गया है, दूसरे को चिढ़ाने की भावना, जेरी द्वारा टॉम के अन्य संभावित शिकारों (जैसे कि बतख, चिड़िया या मछली) को खाए जाने से बचाना, दूसरी बिल्ली से प्रतिस्पर्धा आदि शामिल हैं।

थोड़ी तकरार-थोड़ा प्यार

ऐसा नहीं है कि यह जोड़ी हमेशा लड़ाई ही करती रहती है, कभी-कभी ये दोनों वास्तव में एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह व्यवहार करते भी दिखाई देते हैं। 'जैरी एंड द लॉयन' में जब जेरी को एक शरारत सूझती है और वह मरने का नाटक करने लगता है, जिससे कि टॉम यह सोचे कि उसने जैरी को गोली मार दी है। जैरी को लेटा देखकर टॉम प्राथमिक चिकित्सा किट लेकर दौड़ता हुआ आता है। इससे पता चलता है कि टॉम और जैरी में तकरार के बाद भी प्यार छिपा हुआ है। साथ ही दिलचस्प बात यह है कि कई सारे चित्रों में भी टॉम तथा जैरी एक दूसरे पर मुस्कुराते हुए दिखाए गए हैं, जो प्रत्येक काटरून में दूसरे पर प्रदर्शित अत्यधिक झुंझलाहट के बजाय प्यार-तकरार का रिश्ता अंकित करता है।

जैरी की चालाकी और किस्मत की वजह से टॉम शायद ही कभी जैरी को पकड़ने में सफल हो पाएगा, लेकिन इतना तो अवश्य है कि इन दोनों के दौड़-भाग का यह खेल हमेशा लोगों को गुदगुदाता रहेगा।

टॉम एंड जेरी कौन हैं?

टॉम का असली नाम थॉमस है, जो कि नीली-स्लेटी आंखों वाला ब्रिटिश घरेलू बिल्ला है। जैरी भूरे रंग का छोटा-सा चूहा है। शुरुआती कहानियों में टॉम का नाम जैस्पर और जैरी का जिंक्स था। टॉम को गुस्सा जल्दी आता है, जबकि जैरी अवसरवादी और खुशदिल है। वैसे तो कहा जाता है कि बिल्लियां बड़ी चालाक होती हैं, लेकिन टॉम और जैरी की कहानी में टॉम की हर फुर्ती को जैरी का दिमाग बड़ी आसानी से हरा देता है। हालांकि, हर कहानी में जीत जैरी की होती है लेकिन कहीं अगर जैरी अपनी सीमाएं तोड़ देता है, या कहीं किसी बुराई का साथ दे बैठता है, तो टॉम की विजय भी होती दिखाई देती है।

मनोविज्ञानी कहीं-कहीं इस चूहे-बिल्ली की कहानी को महज़ शरारत नहीं मानते। यह दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कहानी भी बन जाती है। उनका कहना है कि बच्चों को सिर्फ शो का मज़ा लेना चाहिए। किसी भी तरह से ऐसे खेलों को अपने दोस्तों या बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। टॉम एंड जैरी के खेल काल्पनिक हैं, इनकी नकल करना घातक हो सकता है।

जाने डॉल्फिन के बारे में

डॉल्फिन को हम अक्सर मछली कहते है परन्तु वास्तव में डॉल्फिन एक मछली नहीं है। वह तो एक स्तनधारी प्राणी है। जिस तरह व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है वैसे ही डॉल्फिन भी इसी कैटेगरी में आती है। यह एक छोटी व्हेल की ही तरह है। डॉल्फिन का रहने का ठिकाना संसार के समुद्र और नदियां हैं।

डॉल्फिन को अकेले रहना पसंद नहीं है यह सामान्यतः समूह में रहना पसंद करती है। इनके एक समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। हमारे भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है लेकिन गंगा नदी में मौजूद डॉल्फिन अब विलुप्ति की कगार पर है। डॉल्फिन की एक बड़ी खासियत यह है कि यह कंपन वाली आवाज निकालती है जो किसी भी चीज से टकराकर वापस डॉल्फिन के पास आ जाती है।

इससे डॉल्फिन को पता चल जाता है कि शिकार कितना बड़ा और कितने करीब है। डॉल्फिन आवाज और सीटियों के द्वारा एक दूसरे से बात करती हैं। यह 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। डॉल्फिन 10-15 मिनट तक पानी के अंदर रह सकती है लेकिन वह पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती। उसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

केजरीवाल कब तक बचेंगे कोई गारंटी नहीं : स्मृति ईरानी

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कितने समय तक जेल से बाहर रह सकते हैं। स्मृति ईरानी दिल्ली में नवीन शाहदरा जिला कार्यकर्ता संगम में बोल रही थीं और उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि आपको (बीजेपी नेता मनोज तिवारी) और जिला अध्यक्ष को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जिस व्यक्ति ने पहले ही अपने आधे मंत्रिमंडल को जेल भेज दिया है, वह (दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल) कितने समय तक बाहर रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आम आदमी पार्टी (आप) के तीन नेता, जिनमें सत्येन्द्र जैन, मनीष सिसौदिया और संजय सिंह शामिल हैं, विभिन्न मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वर्तमान में जेल में हैं।

ललित झा के टीएमसी के संबंध पर ममता बनर्जी की दो टूक

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य और मास्टरमाइंड ललित झा के बीच कथित संबंधों को खारिज कर दिया और इसे बंगाल की छवि खराब करने की भाजपा की चाल करार दिया। उन्होंने 2001 के संसद हमले की बरसी पर नई संसद में हुए बड़े सुरक्षा उल्लंघन पर प्रकाश डालते हुए इसे एक गंभीर मामला बताया। नेताजी सुभाष बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध एक गंभीर मामला है। यह एक बड़ी चूक थी। केंद्रीय गृह मंत्री पहले ही यह स्वीकार कर चुके हैं। उन्हें इसकी जांच करने दीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के कारण टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन के साथ-साथ 14 अन्य लोगों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित करने को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनका (भाजपा) एकमात्र काम है बंगाल की छवि खराब करना है।

गिरिराज ने राहुल द्वारा घुसपैठ पर दिये बयान पर बोला हमला

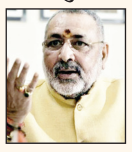

बेगुसराय। केंद्रीय मंत्री और बेगुसराय से लोकसभा सांसद गिरिराज सिंह ने संसद पर हुई घुसपैठ को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दिए गये बयानों की आलोचना की और कहा कि जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने इसकी तुलना किसानों के विरोध प्रदर्शन से की और कहा कि सुरक्षा उल्लंघन में एक टूलकिट गिरोह शामिल था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह वही राहुल गांधी हैं जो अफजल गुरु को फांसी दिए जाने पर जेएनयू गए थे। संसद पर हमले की जांच की जा रही है और साजिश स्पष्ट हो जाएगी और सच्चाई आम जनता के सामने आ जाएगी जैसे किसानों के विरोध के दौरान टूलकिट के रचनाकारों का खुलासा हुआ था। गिरिराज सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य में कोई कानून-व्यवस्था नहीं है और हिंदुओं को हलाल मांस खिलाकर उनकी आस्था को भ्रष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म में सदियों से बाली प्रथा है।

दुख की बात है, सुरक्षा के मुद्दे पर भी राजनीति हो रही: बिड़ला

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सोमवार को कहा कि 13 दिसंबर को सुरक्षा उल्लंघन की घटना की जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है और उन्होंने इस मुद्दे के राजनीतिकरण पर नाराजगी व्यक्त की। मीडिया के अनुसार लोकसभा के स्पीकर ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों से कहा कि संसद की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय के दायरे में है और कुछ विपक्षी सदस्यों का निलंबन 13 दिसंबर की घटना से नहीं बल्कि सदस्यों द्वारा सदन में तख्तियां लेकर आने से संबंधित है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति ने पहले ही अपनी जांच शुरू कर दी है और संसद की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सर्वदलीय बैठक में उन्हें दिए गए कुछ सुझावों को लागू किया गया है। स्पीकर ओम बिड़ना ने कहा कि वह इस मुद्दे पर संसद सदस्यों से परामर्श करना जारी रखेंगे और उनसे अपनी सीट लेने का आग्रह किया। स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा, यह दुखद है कि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। सदन के वेल में आना और नारेबाजी करना सदन की गरिमा के खिलाफ है।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने लॉन्च किया डोनेट फॉर देश अभियान

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश (देश के लिए दान) अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस अभियान पर कहा कि पहली बार कांग्रेस देश के लिए दान करने को कह रही है। खरगे ने कहा, अगर आप लगातार अमीर लोगों पर निर्भर होकर काम करेंगे तो आपकों उनकी नीति माननी पड़ेगी। महात्मा गांधी ने भी देश को आजादी दिलाने के लिए लोगों से चंदा लिया था। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि 18 साल से अधिक उम्र के भारतीय इस अभियान के जरिये 138 रुपये, 1,380 रुपये, 13,800 रुपये या फिर इससे 10 गुने की राशि चंदे के रूप में दे सकते हैं।

इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज दिल्ली में

नीतीश-लालू और तेजस्वी यादव इंडिया की बैठक में होंगे शामिल, आज सीट बंटवारे पर हो सकता है मंथन

नईदिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली आ गए हैं। पटना में जनता के दरबार कार्यक्रम में फरियादों की अर्जी सुनने के बाद मुख्यमंत्री सोमवार शाम को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वे मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ जदयू की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी, सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा मुख्य रूप से शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग सहित अन्य राजनीतिक मुद्दों पर निर्णय होने की संभावना है। इस संबंध में पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी स्पष्ट कर चुके हैं।

इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक मंगलवार को दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में 25 दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राजद सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर चर्चा संभव है। माना जा रहा है कि अब सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ेगी और इस बैठक में सीट शेयरिंग समेत अन्य अहम मुद्दों पर विपक्षी दलों के नेता मंथन करेंगे। बता दें कि यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 6 दिसंबर को ही बुलाई थी। चार राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आते ही कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बैठक बुलाई थी लेकिन कई नेताओं ने व्यस्त कार्यक्रम को लेकर इस बैठक में आने से असमर्थता जता दी थी जिसके बाद बैठक को टाला गया था और 19 दिसंबर की तिथि इस बैठक के लिए तय की गयी थी।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर जोर दिया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार लगातार यह कहते रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में समय बेहद कम है। वहीं भाजपा समय से पहले भी चुनाव करा सकती है। ऐसे में अब जल्द सबकुछ तय कर लेना उचित होगा। वहीं बिहार में अब सियासी समीकरण बदला हुआ है जिसके बाद सीट शेयरिंग में भी कई चीजें अड़चन बन सकती है जिसका समाधान

विपक्षी दलों के नेताओं को निकालना होगा। कई सीटें ऐसी हैं जहां जदयू और राजद आमने-सामने रही हैं। जबकि कई सीटों पर कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। वामदलों की ओर से भी कई सीटों पर दावेदारी पेश करने की तैयारी है। पिछली बार यानी लोकसभा चुनाव 2019 में जब जदयू भाजपा के साथ एनडीए में थी तब 21.81 प्रतिशत वोट पार्टी को मिले थे। भाजपा को 23.58 प्रतिशत वोट मिले थे। जदयू के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई थी।

तीन राज्यों में हार के बाद कांग्रेस पर हमले तेज

गौरतलब है कि हाल में ही आए चुनाव परिणामों में कांग्रेस को हिंदी भाषी राज्यों में बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गयी जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा ने फिर से वापसी कर ली। वहीं कांग्रेस को तेलंगाना में जीत मिली। हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद से ही पार्टी पर हमले शुरू हो गए थे। जदयू और राजद की ओर से साफ कर दिया गया था कि ये हार कांग्रेस की है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को कांग्रेस ने इन चुनावों में शामिल नहीं किया जिसके कारण ये हार हुई।

भाजपा ने किया बैठक फ्लाप होने का दावा

इधर, पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन गठबंधन की पिछली तीन बैठकों की तरह 19 दिसंबर की बैठक भी फ्लॉप होगी। उसमें चाय पार्टी और फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि घटक दलों में प्रमुख आप के नेता अरविंद केजरीवाल विपश्यना ध्यान करने 10 दिन की छुट्टी पर चले गये। शरद पवार की पार्टी टूट चुकी है, ममता दीदी का कोई भरोसा नहीं और नीतीश कुमार कब बीमार हो जाएं, पता नहीं। सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेतृत्व में एकजुट होने का दावा करने वाला विपक्ष तीन हिंदी भाषी राज्यों में करारी हार से हताश है। ये थके-हारे लोग कोई बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष न भोपाल में साझा रैली कर पाया, न गठबंधन की उप-समितियों की बैठक हो पायी। ये लोग भाजपा के विरुद्ध साझा उम्मीदवार भी नहीं तय कर पायेंगे।

टीएमसी नेता बोले-सीट बंटवारें को लेकर होनी चाहिए बैठक

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन पार्टियों के सांसदों के बीच बातचीत हुई। इंडिया गठबंधन नेताओं की बैठक पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता सुदीप बंद्योपाध्याय ने प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी नेता ने कहा, मल्लिकारिजुन खरगे के आवास पर सुबह में होने वाली बैठक नियमित बैठक है। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बैठ तीन बार पहले ही हो चुकी है। इस बाक सीट बंटवारे को लेकर बैठक होनी चाहिए। सीट बंटबारे की प्रक्रिया पहले होनी चाहिए। बैठक परिणाम पर आधारित होता है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 19 दिसंबर को होने वाली है। इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। हालांकि, अभी तक बैठक का एजेंडा आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन सीटों का बंटवारा मुख्य मुद्दा हो सकता है। इंडिया गठबंधन की यह चौथी बैठक होगी। इससे पहले पटना, बंगलुरू और मुंबई में ये बैठकें हो चुकी हैं। इससे पहले छह दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने आवास पर गठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने अन्यत्र व्यस्तता बताते हुए आने से इंकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को होने वाली बैठक में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन समेत सभी प्रमुख नेताओं के आने की उम्मीद है।

देश अब 'गुलामी की मानसिकता से मुक्ति' की घोषणा कर रहा है: मोदी

वाराणसी। प्रधानमंत्री ने कहा , लेकिन, अब स्वर्वेद मंदिर बनारस आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख स्थान बनकर उभरेगा। इससे आसपास के सभी गांवों में व्यवसाय और रोजगार के अवसर बनेंगे, लोगों की उन्नति के रास्ते खुलेंगे।'' श्रद्धालुओं को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र 'स्वर्वेद महामंदिर' का दौरा किया। यहां 20,000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। सात मंजिला इस भव्य महामंदिर की दीवारों पर स्वर्वेद के श्लोक उकेरे गए हैं। स्वर्वेद महामंदिर प्राचीन दर्शन, आध्यात्मिकता और आधुनिक वास्तुकला का एक मिलाजुला रूप है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि आजादी के सात दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घूमा है और देश अब 'गुलामी की मानसिकता से मुक्ति' और अपनी 'विरासत पर गर्व' की घोषणा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र 'स्वर्वेद महामंदिर' का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, ''गुलामी के दौर में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों को ही निशाना बनाया। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते, तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता।

लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं।'' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था और इस तरह की सोच दशकों तक देश पर हावी रही। इसका नतीजा यह हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया। अपनी विरासत पर गर्व करना भूल गया।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''आजादी के सात दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घूमा है। देश अब 'गुलामी की मानसिकता से मुक्ति' और अपनी 'विरासत पर गर्व' की घोषणा कर रहा है।'' उन्होंने

कहा, ''जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था, वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है।''

मोदी ने कहा, ''आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का उदाहरण रहा है और अब सरकार, समाज और संतगण, सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे तीर्थ स्थलों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक ढांचे की दृष्टि से नए रिकॉर्ड भी बना रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''अब बनारस का मतलब है- विकास। अब बनारस का मतलब है - आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है- स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है।'' वाराणसी के विकास पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''वाराणसी में परिवहन संपर्क बढ़ाने के लिए पिछले लगभग नौ वर्ष में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। वाराणसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सड़कें या तो चार लेन की हो गई हैं या फिर छह लेन की बना दी गई हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

आज दुबई में होगी आईपीएल 2024 की नीलामी

नईदिल्ली। फैंस दिल थाम कर बैठ जाएं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के लिए दुबई में कुछ घंटों में बोली लगेगी। वह समय फिर से आ गया है। किस खिलाड़ी पर हमर चलेगा! कई खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला होगा। किन खिलाड़ियों को मिलेगा नया घर? कौन बिना बिके रह जाएगा? टीमें किन खिलाड़ियों के लिए बैंक तोड़ेंगी? क्या कोई आश्चर्यजनक चयन होगा? यहां वह सब कुछ है जो आपको 2024 आईपीएल नीलामी के बारे में जानने की जरूरत है। एक नीलामी...फिर से? क्या यह पिछले वर्ष आयोजित जैसा ही है? आईपीएल 2025 से पहले एक और मेगा नीलामी में जाएगी। 10 आईपीएल टीमों ने खिलाड़ियों के एक सेट को बरकरार रखा है। 77 स्थान के लिए कुल 333 खिलाड़ी शामिल होंगे। आईपीएल 2024 की नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में होगी। नीलामी भारतीय समयानुसार दोपहर 1.00 बजे शुरू होगी। यह 17वीं आईपीएल नीलामी है, आखिरी नीलामी दिसंबर 2022 में होगी। आईपीएल 2024 नीलामी का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा और मंगलवार, 19 दिसंबर को भारत में जियो सिनेमा के माध्यम से ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। आईपीएल संचालन परिषद ने फ्रेंचाइजी को 1166 खिलाड़ियों की सूची सौंपी थी। फ्रेंचाइजी की सलाह के बाद इन खिलाड़ियों की संख्या 333 कर दी गई। इनमें 214 भारतीय और 119 विदेशी खिलाड़ी हैं। दो खिलाड़ी एसोसिएट देशों के भी हैं। इस नीलामी में सभी 10 फ्रेंचाइजी कुल 262.95 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं। जो 77 स्थान उपलब्ध है उनमें से 30 स्थान विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं। अंतिम आईपीएल 2024 नीलामी पूल में 333 खिलाड़ी होंगे, जिसमें 10 फ्रेंचाइजी द्वारा भरने के लिए अधिकतम 77 स्लॉट उपलब्ध होंगे। इनमें से 30 विदेशी खिलाड़ी होंगे, इसमें कुल 214 भारतीय खिलाड़ी और 119 विदेशी खिलाड़ी होंगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 169 अंक टूटा निफ्टी 21,450 के नीचे

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद सोमवार को शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद, इक्विटी बेंचमार्क सूचकांकों ने कमजोर रुख दिखाया। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 169 अंक कमजोर हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 38 अंक की गिरावट दर्ज की गई। व्यापक बाजारों में, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों ने बेहतर प्रदर्शन किया। बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.4 फीसदी बढ़ा, जबकि स्मॉलकैप 0.6 फीसदी बढ़ा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 168.66 अंक यानी 0.24 फीसदी की गिरावट के साथ 71,315.09 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 71,142.29 और 71,552.24 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 38.00 अंक यानी 0.18 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 21,418.65 अंक पर बंद हुआ।

अंबुजा सीमेंट रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स में 6,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी

नईदिल्ली। सीमेंट सेक्टर की अग्रणी कंपनियों में से एक अंबुजा सीमेंट रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स में 6,000 करोड़ (लगभग 723 मिलियन डॉलर) का निवेश करेगी। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि निवेश को आंतरिक रूप से वित्त पोषित किया जाएगा और गुजरात और राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 1,000 मेगावाट की कैपेसिटी हासिल करने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में फंडिंग प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। अदाणी ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से कैपेसिटी वित्त वर्ष 2026 तक हासिल कर ली जाएगी, और इसकी मौजूदा कैपेसिटी 84 मेगावाट बढ़ जाएगी।

प्रेसटॉनिक इंजीनियरिंग के शेयर में पहले ही दिन डबल हुए पैसे

नईदिल्ली। प्रेसटॉनिक इंजीनियरिंग के शेयरों की सोमवार को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त एंट्री हुई। कंपनी मेट्रो रेल रोलिंग स्टॉक, मेट्रो रेल सिग्नलिंग और इंफ्रा प्रोडक्ट्स तैयार करती है। आईपीओ के तहत 72 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए थे। सोमवार को एनएसई एसएमई पर इसकी रुपये के भाव पर एंट्री हुई है यानी कि आईपीओ निवेशकों को 140 फीसदी का लिस्टिंग गेन मिला। वहीं लिस्टिंग के बाद भी शेयरों में तेजी बनी रही, यह बढ़कर 146 रुपये पर पहुंच गया है यानी कि आईपीओ निवेशक अब 100% से ज्यादा 102.78 फीसदी मुनाफे में हैं। निवेशकों के रिस्पॉन्स की बात करें तो प्रेसटॉनिक इंजीनियरिंग का 23.30 करोड़ रुपये का आईपीओ खुदरा निवेशकों के दम पर इस आईपीओ को निवेशकों का तगड़ा रिस्पांस मिला था। ओवरऑल यह आईपीओ 168.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 11-13 दिसंबर के बीच खुला था।

जीएमपीसी सेटेलाइट प्रोवाइडर्स को एडमिनिस्टर्ड कीमत पर मिल सकता है स्पेक्ट्रम

नईदिल्ली। सुनील मित्तल की वनवेब के लिए इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है, माना जा रहा है कि सोमवार को संसद में पेश किए जाने वाले टेलीकॉम बिल 2023 में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस (जीएमपीसी) सेटेलाइट प्रोवाइडर्स को एडमिनिस्टर्ड कीमत के तहत स्पेक्ट्रम आवंटित करने वालों में शामिल किया गया है। वनवेब इस पर जोर दे रहा था, जबकि प्रतिद्वंद्वी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो स्पेक्ट्रम की नीलामी की मांग कर रहा था। वर्तमान में, टेलीकॉम विधेयक 2023 निर्दिष्ट करता है कि जहां तक स्पेक्ट्रम प्रबंधन का सवाल है, सरकार इसे सार्वजनिक हित या अनुसूची 1 की आवश्यकता के मद्देनजर सरकारी उद्देश्यों के लिए नीलामी या प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से टेलीकॉम के लिए आवंटित कर सकती है।

डीडीए का एकाधिकार और बाजार का बदला

शेखर गुप्ता

देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास को समझने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (ड्डष्ठ) का उदाहरण बहुत जानकारीपरक है। यह हमें बताता है कि क्या बदलाव हुआ है और क्या नहीं। यह बदलाव अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। सन 1957 में अपनी स्थापना के बाद से काफी समय तक डीडीए सर्वशक्तिमान रहा। उस दौरान दिल्ली में जमीन एवं उसके विकास पर उसका एकाधिकार था। बहुत कम समय में यह दिल्ली के लिए सोवियत शैली की एक विकास एजेंसी के रूप में विकसित हो गया।

आगे बताऊंगा कि आखिर क्यों मैं कई बार इसे दिल्ली विनाश प्राधिकरण कह कर पुकारता हूं। फिलहाल तो मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि डीडीए ने अपने बनाए मकान बेचने के लिए चमकदार विज्ञापन जारी किए हैं। मैं इस बात से भी खुश हूं कि उसे ग्राहक तलाशने के लिए जूझना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि सत्ता तंत्र का पूरा समर्थन प्राप्त इस संस्था का अंत बाजार के हाथों किस प्रकार हो रहा है।

डीडीए कोई दो-चार मकान बेचने का प्रयास नहीं कर रहा है। शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने गत वर्ष राज्य सभा को बताया था कि ऐसे मकानों की संख्या 40,000 से अधिक है। अनुमान है कि इन अनबिके मकानों की कीमत करीब 18,000 करोड़ रुपये है। यह स्थिति उन डीडीए फ्लैटों की है, जिनके लिए एक समय लोगों को दशकों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। आवेदकों को लॉटरी से फ्लैट आवंटित होते थे। यदि आपका कोई रिश्तेदार ऊंचे पद पर हो या आप किसी खास आरक्षित वर्ग से हों तो यकीनन फ्लैट पाने में मदद मिलती थी। यहां खास आरक्षित वर्ग में सर्वोच्च

न्यायालय के न्यायाधीश तक शामिल थे। एक ऐसे शहर में डीडीए फ्लैट विशेषाधिकार और भगवान नहीं तो भी सरकार का उपहार होते थे, जहां किसी को कुछ भी बनाने का अधिकार नहीं था। वही डीडीए अब खरीदार खोज रहा है। संदर्भ के लिहाज से देखें तो डीडीए के बिना बिके फ्लैटों का मूल्य इस एकाधिकार संपन्न सरकारी विभाग के कुल 'आरक्षित' 9,028 करोड़ रुपये के दोगुने से अधिक है, परंतु क्या आप जानते हैं कि सरकार द्वारा संचालित कारोबार का सबसे पुराना सिद्धांत यही है कि अगर आप खुद को किसी गड्ढे में पाएं तो खुदाई जारी रखें। डीडीए के पास 16,000 से अधिक अनबिके मकान हैं। इनमें से अधिकांश बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में हैं, जहां कोई नहीं रहता। ये मकान बिके क्यों नहीं, किशोर ने इसके लिए मुख्य रिहायशी इलाकों से दूरी, अधिक कीमतें, मेट्रो संपर्क न होना और फ्लैटों का छोटा आकार जैसे अनेक कारण गिनाए थे। सवाल यह है कि आखिर इनके लिए जगह किसने चुनी, कीमतें तय करते समय बाजार का अध्ययन क्यों नहीं किया गया?

यदि आपको लगता है कि इन फ्लैटों को बेचने में नाकाम रहने पर वह नए फ्लैट नहीं बनाएगा तो आप शायद भारतीय राज्य को नहीं जानते। भारत एक ऐसा देश है जो सात दशकों तक समाजवाद के खांचे में पका है। विंस्टन चर्चिल ने क्रिस्टोफर कोलंबस को दुनिया का पहला समाजवादी ठहराते हुए कहा था- उन्हें पता नहीं था, वह कहां थे। यह भी पता नहीं था कि वह कहां जा रहे थे, लेकिन उन्होंने करदाताओं के खर्च पर अपनी यात्रा जारी रखी। शायद यही वजह है कि 2022-23 में डीडीए ने 23,955 नए फ्लैट बना दिए, जबकि पहले के 16,000 फ्लैट्स ही नहीं बिके थे। इसके पीछे उसकी रणनीति अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विविधता लाने का प्रयास है। उसका विचार मूल्य श्रृंखला में ऊपर जाने का भी है। यही वजह है कि नई दिल्ली के मध्यवर्गीय इलाके द्वारका में 14 पेंटहाउस बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत पांच करोड़ रुपये है। कल्पना करें कि आपकी सरकार अभी भी ब्रांडेड कोला पेय, ब्रेड, स्कूटर, टेलीविजन और कंप्यूटर आदि बना रही होती तो क्या आप उन्हें खरीदते? शायद नहीं। हम ऐसा ही सफर तय करते हुए आगे बढ़े हैं। जब जॉर्ज फर्नांडिस ने कोक पर प्रतिबंध लगा दिया था तब हमने 'डबल 7 (77)' कोला बनाया था।

मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर राज्य में शुरू हुए नक्सल उन्मूलन अभियान को मिली बड़ी सफलता

दंतेवाड़ा और बीजापुर इलाके में 11 नक्सली गिरफ्तार

गिरफ्तार नक्सलियों में जन मिलिशिया सदस्य मिच्या लखमू रानी बोदली कैम्प हमले में रहा है शामिल

पुलिस और केन्द्रीय बलों के जवान बस्तर अंचल के संवेदनशील इलाकों में लगातार कर रहे हैं सर्चिंग

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य में नक्सल घटनाओं पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए पुलिस एवं केन्द्रीय बलों के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू हुए सर्चिंग अभियान को आज बड़ी सफलता मिली है।

दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में 11 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। बीजापुर जिले के गट्टापल्ली में थाना कुटरू के पुलिस जवानों के द्वारा जनमिलिशिया सदस्य मिच्या लखमू को पकड़ा गया। मिच्या लखमू 15 मार्च 2007 को रानीबोदली कैम्प हमले में शामिल था।

7 दिसंबर 2009 को ग्राम टुंगेली के ग्रामीण माढ़वी दुलगो के हत्या में भी मिच्या लखमू शामिल रहा है। इसके विरूद्ध थाना कुटरू में दो वारंट भी लंबित है। मिच्या लखमू को बीजापुर न्यायालय में पेश किया गया है।

बीते कुछ दिनों से बस्तर अंचल में नक्सली हमले में आयी तेजी को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की आपात बैठक लेकर इन घटनाओं की रोकथाम और नक्सलियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य में विशेषकर बस्तर अंचल में पुलिस और केन्द्रीय बल के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशील इलाकों में सर्चिंग का अभियान तेज कर दिया गया है। माओवादियों की मौजूदगी को लेकर पतासाजी शुरू कर उनकी धरपकड़ का अभियान शुरू कर दिया गया है।

दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सरहदी क्षेत्र हुर्रेपाल एवं बेचापाल में भैरमगढ़ एरिया कमेटी कामारूर एलओएस कमांडर सोनू आयाम के साथ लगभग 20-25 माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी., दंतेवाड़ा रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक कमललोचन कश्यप, सीआरपीएफ के उप पुलिस महानिरीक्षक विकास कठेरिया एवं पुलिस अधीक्षक गौरव राय के मार्गदर्शन में डीआरजी, बस्तर फाइटर्स दंतेवाड़ा तथा सीआरपीएफ 230 बटालियन यंग प्लाटून नरेली का संयुक्त बल बेचपाल, हुर्रेपाल एवं गहनार के जंगल की ओर सर्चिंग के लिए रवाना किया गया। इस इलाके में पुलिस पार्टी को देखकर कुछ संदिग्ध लोग भागने और छिपने लगे पुलिस पार्टी ने घेराबंदी कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें मोती ओयाम, कारू कड़ती, छोटू हेमला, राजेश कड़ती, सोमारू ओयाम, सुनील माड़वी, माड़का लेकाम, आयतु, कोया हेमला एवं बचलू मड़काम शामिल हैं। यह सभी बेचापाल एवं हुर्रेपाल पंचायत डीएकेएमएस, सीएनएम मिलिशिया के सदस्य है।

गिरफ्तार माओवादियों में सुनील माड़वी हुर्रेपाल पंचायत मिलिशिया का डिप्टी कमांडर है। यह सभी 26 नवम्बर 2023 को भांसी निर्माण कार्य में लगे वाहनों की आगजनी की घटना में शामिल रहे हैं। गिरफ्तार किए गए सभी माओवादियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

जो वादा किया, वो निभाना पड़ेगा

भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के जनता ने बेहद उदार मन के साथ दोबारा सत्ता सौंपी है, इसलिए पार्टी का परम कर्तव्य है कि वह जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए चुनाव में जितने भी लोकभावन वादे किए थे, उन्हें पूर्ण करे। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी भी दी है। प्रधानमंत्री की गारंटी की मर्यादा का पालन बहुत जरूरी है। जनता के मन में तभी विश्वास जाग्रत होगा, जब गारंटी को लागू करने की दिशा में फौरन कार्य शुरू कर दिया जाए । और यह इसलिए भी जरूरी है कि थोड़ी-सी भी लापरवाही हुई तो इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। छह महीने बाद लोकसभा के चुनाव होना है। उस चुनाव की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आने वाले कुछ दिनों में ही भाजपा सरकार के वादे पूर्ण करने की दिशा में कुछ कदम उठ जाए। पिछली कांग्रेस सरकार ने अनेक वादे किए थे। लेकिन कुछ वादों के मामले में तो उसने बुरी तरह पलटी मार ली। हाथ में गंगाजल लेकर भी उसने अपना वचन नहीं निभाया। यही कारण है कि उसका गुरुर मिट्टी में मिल गया और सरकार का पतन सबके सामने है। इसलिए कांग्रेस के पतन को सबक मानकर भाजपा सरकार को अपना काम करना चाहिए। और देश-दुनिया को बता देना चाहिए कि उसने जो वादे किए हैं, उसे सौ फीसदी पूरा किया जाएगा। अगर मगर की, बजट आदि की अब कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो कहा, वह पूरा करना ही नैतिकता है। कोई भी सरकार तभी लंबे समय तक टिक पाती है, जब वह जनता के विश्वास पर खरी उतरती है। छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता को पूरा विश्वास है कि इस बार जो सरकार आई है, वह जनता की सरकार होगी। जनता की हर समस्या का समाधान करेगी ।शराबखोरी की बढ़ती लत पर वह विराम लगाएगी और पहली प्राथमिकता में ही शराबबंदी की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी । आदिवासी मुख्यमंत्री का चयन किया गया है, इसलिए अब मुख्यमंत्री का भी दायित्व है कि वह आदिवासी समाज के उन्नयन के लिए अपनी कार्य योजना बनाए। अब सरकार स्मार्ट नगर से भी आगे बढ़े और स्मार्ट गांव से होते हुए स्मार्ट वनवासी (आदिवासी) जीवन तक पहुंचे। वनबधुओं को हम वनों में रहने की पूरी सुविधा उपलब्ध कराएं। उनकी सहमति से उनका समुचित विकास करें। वन प्रांतर में रहने वाले बन्धुओं को उनकी सुविधा के लिए बाजार मिले। वहां विद्यालय हो। वहां चिकित्सालय हो। और शहर से वनों तक पहुंचने वाले मार्ग पक्के हों। अगर इतना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाँच सालों में कर लेती है, तो यह बहुत बड़ी सफलता होगी। इसका एक सुंदर संदेश देशभर में जाएगा कि सरकार कुछ करने वाली सरकार है ।अगर आदिवासी मुख्यमंत्री का चयन किया गया है तो वह शो-पीस नहीं है । इसके पीछे एक सोची-समझी रणनीति है कि अब हमें शहर और गांव से दूर वन प्रांतर में रहने वाले आदिवासी बन्धुओं का भी उन्नयन करना है। आदिवासी लोक कला संस्कृति के साथी नागर जीवन से जुड़ी कला-संस्कृति और साहित्य के उन्नयन की दिशा में गंभीर होने की जरूरत है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस छत्तीसगढ़ की राजभाषा छत्तीसगढ़ी है ,उस छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग को कांग्रेस सरकार एक अध्यक्ष तक नहीं दे पाई और पाँच साल निकल गए!! इस दिशा में भाजपा सरकार को चंद महीनों में एक अध्यक्ष देना ही चाहिए। बहरहाल, छत्तीसगढ़ में तो बहुआयामी विकास तो करना ही है, मध्यप्रदेश और राजस्थान में भी जो वादे हुए हैं, उन वादों को लागू करके वहां भी जन विश्वास को अर्जित करना है। और मुझे क्या, हर नागरिक को लगता है कि इस बार हर वादा पूर्ण होगा। इन वादों की बुनियाद पर ही सन 2024 को एक बार फिर अब विजय की तीसरी मंजिल खड़ी हो सकेगी।

बाबा के बताए रास्ते पर चलकर ही समाज एवं राष्ट्र का विकास संभवः मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री साय लालपुर धाम में गुरू घासीदास जयंती समारोह में हुए शामिलमंदिर और जैतखाम की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की गुरू घासीदास जयंती समारोह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के लालपुर धाम में आयोजित गुरू घासीदास जयंती एवं तीन दिवसीय मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यहां बाबा गुरू घासीदास मंदिर एवं जैतखाम में पूजा-अर्चना कर राज्य की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए बाबा का आशीर्वाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री श्री साय का कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पंथी नर्तक दल द्वारा पंथी नृत्य के माध्यम से भव्य स्वागत किया गया। वहीं सतनामी कल्याण समिति बंधवा लालपुर के पदाधिकारीगण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पुष्प माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा के बताये सत्य के रास्ते पर चलकर छत्तीसगढ़ सरकार हमारे पुरखों और महापुरूषों के खुशहाल छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करेगी।

उन्होंने गुरु घासीदास जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा गुरू घासीदास का संदेश आज के संदर्भ में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। बाबा ने उस समय के समाज में प्रचलित ऊंच-नीच, भेद-भाव, छूआछूत का प्रबल विरोध किया। मनखे-मनखे एक समान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि आपसी मतभेद से नहीं बल्कि सामाजिक समरसता से ही समाज एवं देश का विकास होता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार जयंती समारोह में शामिल होने का मौका मिला है। बाबा घासीदास का जन्म 18वीं सदी में छत्तीसगढ़ की धरती में हुआ था। बाबा ने पूरे विश्व को मनखे-मनखे एक समान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि हम हर साल 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाते है। बाबा गुरु घासीदास का ही आशीर्वाद है, कि मुझ जैसे एक छोटे से किसान को सीएम का दायित्व मिला है।

ईवीएम पर नहीं 'भूपेश का भरोसा'!.. कहा बैलेट पेपर से चुनाव करने में क्या हर्ज है?

रायपुर. देश के भीतर जब कभी भी चुनाव परिणाम सामने आते है अपने साथ कई विवाद भी साथ लाते है। इस तरह कहा जाए तो मतपेटियों से परिणाम ही नहीं बल्कि कई विवाद भी बाहर आते है। सबसे आम विवाद मतदान की प्रक्रिया के लिए अपनाये जाने वाले ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर है। ईवीएम अक्सर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के निशाने पर रहा है।

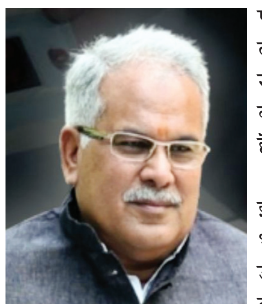

पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता हर चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का राग अलापते है। जिन राज्यों में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं होते वह इसे लेकर ज्यादा रार नजर आता है। बात करें पिछले दिनों सामने आएं विधानसभा चुनाव परिणाम की तो विपक्ष के नेताओं का निशाना पर इस बार भी ईवीएम था। बात करें छत्तीसगढ़ की तो अबतक कांग्रेस के छोटे नेता ही ईवीएम पर सवाल उठा रहे तो वही अब सूबे के पूर्व मुखिया भूपेश बघेल में इस लिस्ट में शुमार हो गए है।

हालांकि उन्होंने साफतौर पर ईवीएम की मुखालफत तो नहीं की लेकिन उनका कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में हर्ज कैसा? और इस तरह उन्होंने भी मतदान के मशीन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए है।

दरअसल आज प्रदेश भर सतनामी समाज के पूजनीय संत शिरोमणी बाब गुरुघासी दास की जयंती मनाई जा रही है। समाज की ओर से आयोजित जयंती कार्यक्रमों में राजनेता भी पहुँच रहे है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी आज इस सिलसिले में भिलाई के सतनाम भवन सेक्टर 6 पहुंचे हुए थे। यहाँ उन्होंने बाबा घासीदास की गुरुगद्दी की पूजा कर आशीर्वाद लिया और इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कई सियासी सवालों के जवाब दिए।

ईवीएम की गड़बड़ी की आशंका से जुड़े सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका सभी को है। ऐसे में एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या हर्ज है? नई सरकाए के कामकाज पर पूछे गए सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि 5 दिन में समीक्षा करना ठीक नहीं होगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

न्याय योजना की राशि नहीं जारी करना किसान विरोधी

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के द्वारा न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों को नहीं देने का कांग्रेस ने विरोध किया है, भाजपा आदतन किसान विरोधी है इसीलिए किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त से वंचित कर रही है। यह प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसानों के साथ अन्याय है। असल में भाजपा किसानों से की गई वादा को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही है इसीलिए अभी तक किसानों से 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ और 3100 रुपए क्विंटल की दर पर खरीदी करने का आदेश जारी नहीं किया गया है। अब न्याय योजना की चौथी किस्त की रखी हुई राशि को भी अन्य मद में खर्च कर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने में लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि तत्काल किसानो के खाता में जमा करना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने बीते खरीफ वर्ष में न्याय योजना के माध्यम से 24 लाख से अधिक किसानों के खाता में तीन किस्तों में 3704 करोड रुपए की राशि जमा करवा चुकी है और चौथी किस्त की राशि की व्यवस्था भी कर के रखी हुई है। मुख्यमंत्री को सिर्फ बटन दबाकर उस राशि को किसानों के खाता में सीधा जमा करवाना है। कांग्रेस की सरकार ने धान की खरीदी प्रति क्विंटल 2500 रू से अधिक दाम में कर 5 वर्षों में न्याय योजना के माध्यम से 23803 करोड रुपए किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया है।

शीतकालीन सत्र आज से, केवल प्रवेश पत्र धारी ही करेंगे प्रवेश

रायपुर। चार दिन पहले लोकसभा सदन में युवकों के कूदकर धमाचौकड़ी मचाने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा प्रशासन ने भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। सत्र अवधि के दौरान केवल प्रवेश पत्र धारी लोगों को ही विधान सभा परिसर में प्रवेश की पात्रता रहेगी। प्रवेश पत्र धारी व्यक्तियों को अपने संस्थान का परिचय पत्र या आधार कार्ड रखना आनिवार्य होगा। छठवीं विधानसभा का प्रथम शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। सत्र के प्रथम दिवस सभा में विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। 20 दिसम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद का अभिभाषण होगा। विधान सभा परिसर एवं सभी दीर्घाओं में सुरक्षा कर्मियों द्वारा कड़ी नजर रखी जायेगी। केवल विधायकों को ही वीआईपी गेट तक जाने की अनुमति होगी। विधायकों के साथ आये कार्यकर्ता एवं उनके परिजनों के लिए विधान सभा परिसर स्थित प्रेक्षागृह में बड़ी की स्क्रीन लगाकर सदन की सीधी कार्यवाही देखने की व्यवस्था की गयी हैं। उनका प्रवेश गेट क्रमांक-1 से होगा। नवनिर्वाचित सदस्यों के स्वागत में विधान सभा परिसर को फूल मालाओं एवं रंगोली से सजाया जा रहा है। बरौंडा चौक का नये तरीके से सौन्दर्गीकरण और विधान सभा परिसर को लोककला एवं लोक संस्कृति युक्त पेंटिंग से सजाया जा रहा है।

रायपुर रेल मंडल के कर्मी हुए सम्मानित

रायपुर। केंद्रीय रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर के विभिन्न जोनों/मंडलों, उत्पादन इकाइयों और रेलवे पीएसयू के 100 रेलवे कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार' (एवीआरएसपी) से सम्मानित किया, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दो रेलकर्मी अमिताभ चौधरी, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता, पीपी यार्ड, भिलाई तथा श्री प्रमोद कुमार, आरक्षक, रेलवे सुरक्षा बल, गोंदिया शामिल थे । उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के बीच उत्कृष्ट सेवाएँ एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 21 शील्ड भी प्रदान कीं, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के बेहतर प्रबंधन हेतु ट्राफिक ट्रांसपोर्टेशन शील्ड तथा रॉलिंग स्टॉक के बेहतर प्रबंधन के लिए बेस्ट 'रॉलिंग स्टॉक शील्ड' से सम्मानित किया गया । पुरस्कार/शील्ड नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित 68वें रेलवे सप्ताह केंद्रीय समारोह में प्रदान किए गए । इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ और सदस्य, जोनल रेलवे के महाप्रबंधक और रेलवे की उत्पादन इकाइयों और रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख उपस्थित थे ।

विजय मर्चेंट ट्रॉफी,9 विकेट से चंडीगढ ने हराया छत्तीसगढ़ को

रायपुर। बी.सी.सी.आई. के मेन्स अंडर-16 के तहत विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2023-24 केअंतर्गत टीम सोमवार को ग्रुप सी का चौथा मैच डेक्कन जिमखाना ग्राउंड पुणे में चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ के बीच खेल गया जिसमें चंडीगढ़ की टीम ने छत्तीसगढ़ को 9 विकेट से पराजित कर दिया। छत्तीसगढ़ की टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पहली पारी में 56.5 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर 274 रन बनाये। छत्तीसगढ़ टीम की ओर से नितांत सिंह ने नाबाद 135 रन तथा आदित्य गुहा ने 56 रन की पारी खेली। चंडीगढ की ओर से मार्कंडेय पांचाल ने 5 विकेट तथा अंकन लटका ने 3 विकेट प्राप्त किये। चंडीगढ़ ने अपनी पहली पारी 123.3 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 526 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। चंडीगढ की ओर से मीत दहीया ने 159 रन, गगनप्रीत ने 95 तथा इहित ने 83 रन तथा रुपेष यादव ने 53 रनों का योगदान दिया। छत्तीसगढ़ की ओर से धनंजय नायक ने 4 एवं फैज खान ने 2 विकेट प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ अपनी दुसरी पारी में 81.2 ओवरों में 277 रन बनाकर आउट हो गयी। छत्तीसगढ़ की ओर से अमेया मोरे ने 73 तथा आदित्य गुहा ने 56 रनों का योगदान दिया। चंडीगढ की ओर से मार्कंडेय पांचाल ने 4 विकेट प्राप्त किये। 26 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चंडीगढ

सड़क पर मलमा गिराया, 2 लोगों पर पन्द्रह हजार जुर्मानाण

रायपुर। नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 2 में जनशिकायत मिलने पर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा फाफाडीह मुख्य मार्ग पर बड़ी मात्रा में मलमा गिराए जाने पर स्वास्थ्य अधिकारी रवि लावनिया ने स्थल पर भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी देते हुए सम्बंधित व्यक्ति जयराम दास रोहरा पर तत्काल 10000 रूपये का जुर्माना किया।

इसी तरह खमतराई से भनपुरी मुख्य मार्ग में बड़ी मात्रा में मिट्टी गिराए जाने पर नगर निगम जोन 1 के सहायक जोन स्वास्थ्य अधिकारी उमेश नामदेव ने स्थल पर भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी देते हुए कल्याण हॉस्पिटल फाफाडीह के समीप के क्षेत्र के निवासी सम्बंधित व्यक्ति जयराम दास रोहरा पर तत्काल 5000 रूपये का जुर्माना किया एवं प्राप्त जनशिकायत का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के अनुपालन में दिनांक 19 दिसम्बर 2023 संत तारण तरण जयंती के अवसर पर नगर पालिक निगम रायपुर के परिक्षेत्र में स्थित पशु वध शाला गृह एवं मांस - मटन बिक्री दुकानों को बन्द रखे जाने का आदेश नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया है। उक्त अवसर पर किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जप्त कर कार्यवाही की जायेगी और संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी। उक्त अवसर पर नगर पालिक निगम रायपुर के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक जोन स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षकगण उपरोक्त आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

प्रदेश के जेलों में निरूद्ध प्रत्येक महिला बंदियों एवं उनके बच्चों तक पहुंचे खुशीः भादुड़ी

रायपुर। छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर एवं खुशी फाउण्डेशन के संयुक्त तत्वावधान में 17 व 18 दिसम्बर को केन्द्रीय जेल, रायपुर में निरूद्ध महिला बंदियों एवं उनके बच्चों के उत्थान के संबंध में आयोजित उक्त दो दिवसीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, न्यायमूर्ति, छग उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, अतिथि डॉ. व्ही.सी. विवेकानंदन, कुलपति, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नवा रायपुर एवं अध्यक्षता श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, संस्थापक, खुशी फाउन्डेशन के उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

उक्त समापन सत्र के अवसर पर - माननीय न्यायमूर्ति के अलावा प्रमुख रूप से श्री अब्दुल ज़ाहिद कुरैशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर सहित अनेक न्यायाधीशगण, अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन खुशी फाउन्डेशन की ओर से श्रीमती केसर सिद्दीकी द्वारा किया गया एवं उनके द्वारा उक्त कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य न्यायाधीशगण, पुलिस विभाग, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स एवं महिला बंदियों व प्राधिकरण परिवार के साथ खुशी फाउण्डेशन के सदस्यगण का अभिनंदन किया गया। उक्त कार्यक्रम में विधि छात्रों के द्वारा साइबर क्राइम पर एक नुक्कड़ नाटक कर आज कल होने वाले ओ.टी.पी. शेयर कर बैंक खाता फ्रॉड केस, मोबाइल हैक, स्कैम, फोटो वायरल सोशल मीडिया में हाने एवं ए.आई का दुरूपयोग से रोकने संबंधी नाटक कर अपना ध्यान आकृष्ट किया गया एवं इससे बचने के तरीके बताये गये। किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचने हेतु जागरूक किया गया। केन्द्रीय जेल महिला प्रकोष्ठ में निरूद्ध महिला बंदियों के छोटे-छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। महिला बंदियों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुत की, जिस पर माननीय न्यायमूर्ति द्वारा उनको सम्मान भी प्रदान किया गया। माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी द्वारा बताया गया जो साइबर क्राइम पर जो नुक्कड़ नाटक पेश किया है उसके माध्यम से हम ही नहीं पूरा प्रदेश और देश जागरूक होगा क्योंकि छोटे छोटे प्रलोभनों में आकर कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है। इसीलिए साइबर क्राइम से बचने के लिए उक्त क्राइम की जानकारी रखते हुए सतर्क रहें।

महिला चैंबर का फूड फेस्टिवल व उद्यम सम्मेलन हुआ

रायपुर। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सभागार में आयोजित महिला चेंबर द्वारा आयोजित फूड फेस्टिवल व महिला उद्यमी

सम्मेलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वावलंबी भारत अभियान की टीम ने महिला उद्यमियों को उद्यम में रजिस्ट्रेशन, बैंक लोन, सब्सिडी आदि की जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जैन संगठन की महिला शाखा द्वारा मंगलाचरण से हुआ। उद्घाटन महिला चैंबर की महामंत्री श्रीमती पिंकी अग्रवाल, मंत्री शंकर बजाज, समाज सेविका गजाला खान, लक्ष्मी सेन, शंकर नगर जैन श्री संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रेम लुणावत,कैट के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष जितेंद्र दोषी,युवा चैंबर से जय नानवानी, कांति पटेल, स्वावलंबी भारत अभियान की मंजरी बक्शीने किया। स्वावलंबी भारत अभियान की टीम ने महिला उद्यमियों को उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन, बैंक लोन व सब्सिडी की जानकारी प्रदान की। फायरलेस कुकिंग कंपटीशन में प्रथम स्थान पर आयुषी मुथा, द्वितीय सुशीला सोनगरा, तीसरे स्थान पर सपना जैन व चतुर्थ निधि खंडेलवाल रही। जज थी श्रीमती पारुल मनीष जैन व सुश्री दिशा जैन।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.